● वर्ष-2
● अंक-278
रायपुर, गुरुवार
13 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों ✍ शशांक शर्मा

मोहन मरकाम की छुट्टी दीपक बैज प्रदेशाध्यक्ष

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आखिरकार बदल दिए गए। मोहन मरकाम के स्थान पर बस्तर के सांसद दीपक बैज को प्रदेश का नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो इस बात की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि मोहन मरकाम की बदला जाएगा लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित बैठक में जब टी एस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय के साथ अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ तो लगा विधानसभा चुनाव तक मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। अब अचानक दीपक बैज के मान की घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष बदलने के निर्णय से केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात पर मुहर लगा दी है। इस बात की चर्चा तो साल भर पहले से चल रही थी कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। पूर्व प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में संगठन और सत्ता के बीच तालमेल के अभाव को लेकर बहस भी हो गई थी। मुख्यमंत्री बैठक के बीच में चले गए थे। इसके बाद लगातार मोहन मरकाम ने संगठन पर मुख्यमंत्री को हावी होने नहीं दिया। प्रदेश महामंत्री प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला को अचानक हटाकर अमरजीत चावला को प्रभार सौंप दिया था, इस निर्णय से भी संगठन की गुटबाजी को हवा मिली। मुख्यमंत्री सहित कई नेता प्रदेशाध्यक्ष के निर्णय से खुश नहीं थे। जब ढ़ाई ढ़ाई साल का प्रकरण चल रहा था, विधायक भूपेश बघेल का समर्थन दिल्ली जा रहे थे तब भीमोहन मरकाम ने अपने को तटस्थ रखते हुए दिल्ली नहीं गए थे। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ था उस समय भी समितियों की सूची को लेकर मतभेद उभरे थे। पिछले दिनों मोहन मरकाम ने संभागीय प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी जिसे प्रदेश प्रभारी शैलजा ने खारिज कर दिया। प्रदेश प्रभारी ने संगठन महामंत्री अमरजीत चावला के स्थान पर रवि घोष को प्रभारी महामंत्री बनाने का निर्णय लिया। लेकिन प्रभारी के आदेश को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खारिज कर दिया था। तब से मोहन मरकाम के अध्यक्ष की कुर्सी पर तलवार लटक रही थी। हालांकि मोहन मरकाम के अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त हो चुका था लेकिन चुनाव करीब होने के कारण लग रहा था, वे बदले नहीं जायेंगे। अब मोहन मरकाम को हटाएंजने के बाद कांग्रेस संगठन में फिर मतभेद बढ़ेंगे। स्ववभाविक तौर पर नए अध्यक्ष मोहन मरकाम को टीम को बदलना चाहेंगे। ऐसा हुआ तो नेताओं के घटक में नाराजगी बढ़ेगी। चुनावके पहले बस्तर संभाग में कांग्रेस का एक और मरकाम गुट तैयार हो गया है। नाराज मोहन मरकाम कोंडागांव से अपना विधानसभा चुनाव लडेंगे तो इस पर भी गुटबाजी का असर हो सकता है।

पंचायत के नतीजे में तृणमूल को नुकसान

जिला परिषद में भाजपा की सीटों में मामूली इजाफा, सीपीएम- कांग्रेस पिछड़े

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। राज्य में कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इनमें 42 हजार से ज्यादा सीटों पर टीएमसी जीत चुकी है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और उसने 9,223 सीटों पर जीत हासिल की है। जिला परिषद की 928 सीटों में से टीएमसी को 764 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा 25 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। पंचायत समिति के नतीजों पर नजर डालें तो कुल 9,730 में से 5,898 सीटों पर टीएमसी या तो जीत हासिल कर चुकी है या फिर आगे है। भाजपा को अबतक 706 सीटों पर जीत हासिल हुई है।

इसे समझने के लिए हमने 2013 और फिर 2018 में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया। 2013 में मुख्य लड़ाई टीएमसी बनाम सीपीआई थी। तब टीएमसी ने पंचायत चुनाव में 80 फीसदी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में टीएमसी की जीत का ये आंकड़ा बढ़कर 90 प्रतिशत से ज्यादा हो गया। 2018 में ग्राम पंचायत की 48649 में से 38118 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। मतलब ग्राम पंचायत की 78.35 फीसदी से ज्यादा सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीते थे। भाजपा के हिस्से 5779 (11.87 फीसदी) , सीपीएम के 1713 और कांग्रेस के 1066 सीटें आईं थीं। 1960 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल

की थी।

इसी तरह पंचायत समिति की 9,217 सीटों में से 8,062 (87.46 फीसदी) पर टीएमसी, 769 सीटों (8.34 फीसदी) पर भाजपा, 129 सीटों पर सीपीएम और 133 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 22 सीटों (2.66 फीसदी) पर भाजपा, सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट गई थी। कांग्रेस के छह उम्मीदवार चुनाव जीते थे।

पंचायत समिति की बात करें तो कुल 9,730 में से टीएमसी के खाते में 5898 सीटें (60.61 फीसदी) आ चुकी हैं। पिछली बार के मुकाबले टीएमसी को करीब बीस फीसदी का सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इस बार भाजपा के खाते में 706 सीटें आईं हैं। इसमें भाजपा को करीब एक प्रतिशत सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार सीपीएम और कांग्रेस को इसमें अच्छी बढ़त मिली है। वहीं, निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों का भी पंचायत समिति के चुनाव में दबदबा देखने को मिला है।

ग्राम पंचायतों में भी घट गई टीएमसी की सीटें

इस बार ग्राम पंचायत की कुल सीटें 63,229 हैं। इनमें 42,097 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। मतलब 66.57 फीसदी सीटों पर ही टीएमसी को जीत मिली है। 2018 के मुकाबले इसमें करीब 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है। वहीं, भाजपा ने 9223 सीटों (14.58त्न) पर विजय हासिल की। 2018 से तुलना करें तो भाजपा को इस बार करीब तीन फीसदी सीटों का फायदा हुआ है।

बंगाल जिला परिषद चुनाव की बात करें तो 928 में से 764 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है। मतलब परिषद की 82.32 प्रतिशत सीटों पर अकेले टीएमसी का कब्जा है। पिछली बार जिला परिषद की 96.12 प्रतिशत सीटें टीएमसी के खाते में गईं थीं। मतलब इसमें भी टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ा है।

भाजपा ने पिछली बार 2.66 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 2.69 प्रतिशत सीटों पर पार्टी ने कब्जा जमाया। मतलब पिछली बार के मुकाबले भाजपा को मामूली बढ़त मिली है। वहीं, इस बार चार पर सीपीएम+, 12 पर कांग्रेस को जीत मिली है। एक सीट अन्य के खाते में गई है। बड़ी जीत के बावजूद टीएमसी की सीटें घटी हैं।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के परिणाम अब सामने आ रहे है जिसमें टीएमसी का दबदबा एक बार फिर साफ दिख रहा है। वहीं अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कदाचार का आरोप लगाने वाली तीन याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों से निपटने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव और नतीजों की घोषणा उन मामलों के संबंध में उसके अंतिम आदेशों के अधीन होगी, जिनकी वह मतदान के दिन चुनावी कदाचार के आरोपों पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि अब मामला अदालत के पास है, अब चुनाव का संचालन और परिणामों की घोषणा, इस रिट याचिका में पारित किए जा सकने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये

पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथी परिवार के एक-एक व्यक्ति को होमगार्ड में नौकरी देने का एलान किया है। इसके साथ ही केंद्र पर उठाए सवाल, पूछा- जब मणिपुर जल रहा था, तो कहां थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट देने की बात कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणा की कि चुनावी हिंसा में जिन 19 लोगों की मौत हुई है, उन्हें 2-2 लाख रुपये मुआवजा और एक स्पेशल होम गार्ड की नौकरी दी जाएगी। इनमें टीएमसी के 10 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।

जम्मू। दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित अमरनाथ मंदिर के लिए 7,800 से अधिक तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था बुधवार को यहां आधार शिविर से रवाना हुआ।

विश्व चुनाव निकाय संघ बैठक में फर्जी खबरों का मुद्दा उठा

■ **फर्जी खबरों के मुकाबले के लिए मिलकर काम करें चुनाव प्रबंधन निकाय- राजीव कुमार**

नई दिल्ली। फर्जी खबरों का असर किस तरह से किसी के निजी जीवन से लेकर राजनीति को प्रभावित कर सकता है, यह किसी से छुपा नहीं है। वहीं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कोलंबिया में विश्व चुनाव निकाय संघ (ए-वेब) के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में फर्जी खबरों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ए-वेब जैसे मंचों के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन निकाय फर्जी खबरों का मुकाबला करने सहित गंभीर चुनौतियों पर मिलकर काम कर सकते हैं, जो दुनिया भर में चुनावी अखंडता को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं।

बैठक में भाग लेते हुए, उन्होंने कहा कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने और

महत्वपूर्ण पहल करने वाले चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए ए-वेब वैश्विक पुरस्कार स्थापित करने की भी वकालत की, जिससे लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले। विश्व चुनाव निकाय संघ दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है। नेशनल सिविल रजिस्ट्री, कोलंबिया द्वारा बुधवार को क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। जिसमें चुनावों से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों जैसे मुद्दे पर चर्चा होती है।

ए-वेब पोर्टल बनाने की वकालत

राजीव कुमार ने कहा कि एक ए-वेब पोर्टल स्थापित करने के चुनाव आयोग के प्रस्तावों को उठाया, जो चुनावी सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनावी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में सदस्य चुनाव प्रबंधन निकायों द्वारा की गई पहलों के सजोने का काम करेगा और ए-वेब ग्लोबल की स्थापना करेगा। 11वीं ए-वेब कार्यकारी बोर्ड की बैठक के मौके पर, ईसी की इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र प्रणाली पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। भारत और दक्षिण कोरिया ने चुनाव प्रशासन के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

प्रमुख समाचार

यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा पर बहस, भारत की आपत्ति

नई दिल्ली। मणिपुर में जातीय हिंसा पर बुधवार को यूरोपीय संसद में बहस होने से पहले भारत ने ईयू को साफ संदेश दिया है और कहा कि यूरोपीय संघ सांसदों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह

देश का बिल्कुल आंतरिक मामला है। मणिपुर की स्थिति पर एक प्रस्ताव ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय संघ की संसद में पेश किया गया था और जिस पर बुधवार को बहस की जानी है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि संबंधित यूरोपीय संघ के सांसदों से संपर्क किया और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भारत का बिल्कुल आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को पता है कि ब्रुसेल्स में ईयू संसद में क्या हो रहा है। बता दें कि मणिपुर में करीब दो महीने से खासकर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। विपक्षी दल सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर में तीन मई से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय झड़पें देखी जा रही हैं। हिंसा और आगजनी की व्यापक घटनाओं से राज्य में संकट गहराता जा रहा है।

राहुल का नया ठिकाना होगा पूर्व सीएम शीला दीक्षित का घर

नई दिल्ली। गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सांसद पद अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिसके बाद

उनका आवास भी उनसे छिन गया था। वहीं अब राहुल गांधी जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी जानकारी सूत्रों ने बुधवार को दी। कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अभी दक्षिण दिल्ली के बी2 निजामुद्दीन पूर्व स्थित इस घर में रह रहे हैं। नेता के करीबी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी फिलहाल अपने घर को उसी इलाके में दूसरी इमारत जो शीली दिक्षित की है उसमें शिफ्ट करने वाले हैं जिसकी प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह सुरक्षा की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को जेड-प्लस सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि राहुल फिलहाल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रह रहे हैं।

अमरनाथ यात्रा में साजिश नाकाम, पांच आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए बड़गाम में पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई हथियार भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार पांचों

आतंकी लश्कर-ए-ताइबा से जुड़े हुए हैं। वह अमरनाथ यात्रा में खलल डालना चाहते थे। बुधवार को एक अधिकारी ने बताया कि बड़गाम के खाम इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उनका पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। जब टीम ने कार्रवाई की तो एक ठिकाने पर पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि पांचों जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षाबलों पर हमला और अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की साजिश रच रहे थे। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आतंकियों की पहचान रऊफ अहमद, हिलाल मलिक, तौफीक डार, दानिश अहमद और शौकत अली के रूप में हुई है।

ट्रेन हादसे के बाद कार्रवाई, संस्पेंड किए गए सात कर्मचारी

भुवनेश्वर। दो जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास तीन ट्रेनों की टक्कर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस हादसे में 293 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हो गए। इसके बाद सरकार ने जांच बैठाई कि कमी कहां थी ताकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। इसके बाद रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे ने अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए रेलवे के तीन कर्मचारियों समेत सात कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि अगर अधिकारी सतर्क होते तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। रेलवे ने अब तक सात कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें तीन कर्मचारी वो भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। नियमों के मुताबिक, 24 घंटे के लिए गिरफ्तार किए गए कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। इससे पहले, सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया था। उन्हें बुधवार से सीबीआई ने चार दिन की और रिमांड पर लिया है।

आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या की जांच ष्टक्चढ्ढ से कराने की मांग

बेंगलुरु। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या की उचित जांच सरकारी एजेंसी या सीबीआई से तत्काल कराने

की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया, 5 जुलाई 2023 को बेलगावी के चिक्कोडी में दिगंबर जैन मुनि आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की हत्या की खबर सुनकर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित और हैरान होंगे। आचार्य कामकुमार को आखिरी बार उनके भक्तों ने 5 जुलाई को रात लगभग 10 बजे देखा था। आचार्य कामकुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ने चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पत्र में कहा गया है, %आचार्य कामकुमार की निर्मम हत्या से पूरे देश का दिगंबर जैन समाज क्षुब्ध और स्तब्ध है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उचित सरकारी एजेंसी या सीबीआई द्वारा इस भयावह हत्या की उचित जांच की जाए। दोषियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और न्याय की सहायता के लिए कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए और पूरे देश के जैन समुदाय को इस दुख से राहत दिलाना चाहिए।

महाराष्ट्र की सियासत में फंसा 34 का फेर, मुसीबत में हैं शिंदे गुट के विधायक

आशीष तिवारी

महाराष्ट्र की सियासत में मचा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी तूफान की जद में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक ही आ रहे हैं। मंत्रालय को लेकर छिड़ी जंग में अब नए समीकरण शिंदे के साथ आए विधायकों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट न मिलने का भी बनने लगा है। दरअसल दो दिन पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया कि उसके बाद शिंदे गुट के विधायकों में खलबली मची हुई है। शिंदे गुट के विधायकों को अब डर सता रहा है कि अगर वह लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बने रहे, तो कहीं ऐसा न हो अजीत पवार के गठबंधन में शामिल होने से उनकी सियासी गणित डगमगा जाए और आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट ही ना मिले। दरअसल में सियासी गणित में टिकटों की दावेदारी ऐसी हो रही है कि शिंदे गुट के 40 विधायकों में सब को टिकट मिलने का संकट पैदा हो रहा है।

यह खेला है अजीत पवार ने दांव

महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेता अजित पवार ने आते ही सियासी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। अजित पवार ने आने वाले विधानसभा के चुनावों में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अजित पवार की मान ली जाती है, तो यह एकनाथ शिंदे उनके साथ आए विधायकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु शीतोले कहते हैं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में अगर समूचे महाराष्ट्र की तकरीबन 35 फ़ीसदी से ज्यादा सीटों पर अजित पवार चुनाव लड़ने का दावा करेंगे, तो बची हुई 65 फ़ीसदी सीटों पर टिकट की जंग भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में होगी। चूंकि

महाराष्ट्र में 2019 के हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी में 164 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में उसकी दावेदारी इस बार भी उतनी ही सीटों की तो होगी।

फंसा है 34 की सियासत का फेर

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनावों में सीटों की गणित के बीच में एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों के सियासी सफर पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा पिछले चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 164 विधानसभा सीटों के साथ मैदान में हाथ आजमाया था। आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी योजना के मुताबिक उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 164 विधानसभा सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है, तो बची सीटों पर अपने सहयोगियों को उसे चुनाव लड़ाना होगा। हाल में ही एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेता अजित पवार ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। ऐसे में एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को जोड़ा जाए तो 254 सीटों पर तो सिर्फ यही दो पार्टी की दावेदारी मानी जा रही है। प्रदीप सिंह कहते हैं अब बचती हैं महज 34 सीटें। बस महाराष्ट्र की सियासत में यही 34 सीटों की सियासत का फेर अब भारी पड़ने वाला है। क्योंकि यह संख्या तो एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों की संख्या से भी कम है।

सियासी जानकार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के गठबंधन में 34 सीटों का सियासी फेर बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। जानकारों का कहना है कि भाजपा की पुरानी 164 सीटें और अजित पवार की ओर से मांगी गई 90 सीटों के बाद बच रहीं 34 सीटें, तो एकनाथ शिंदे के साथ आए 40 विधायकों का कोटा भी नहीं पूरा कर पा रही हैं। बस यही सबसे बड़ा पेंच अब एकनाथ शिंदे के साथ फंस रहा है और उनके विधायकों को अखरने लगा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, उनको भी अब आने वाले चुनावों में टिकट मिलने का संकट हो रहा है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रहे हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद विनायक राऊत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ गए आठ से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जो विधायक शिंदे के साथ हैं उनको टिकटों के सियासी उलटफेर में अपना भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शीतोले कहते हैं कि अगर अजित पवार को अपनी मांगी गई तय संख्या के मुताबिक सीटें मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों के लिए दिक्कतें तो पैदा ही होने वाली हैं।

अजित पवार की 90 सीटों की मांग

महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा यह भी हो रही है कि आखिर अजित पवार 90 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अजित पवार के साथ तो इस वक्त उनकी पार्टी से जुड़े हुए सभी 53 विधायक भी नहीं है। इसके पीछे का तर्क देते हुए अजीत पवार के साथ गए एक वरिष्ठ एनसीपी नेता कहते हैं कि उनके साथ एनसीपी के जो विधायक नहीं आए हैं, वह भी उनके साथ हैं। अजित पवार सभी 53 विधायकों का अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि अजित पवार उन सभी 53 सीटों पर टिकट की दावेदारी तो कर ही रहे हैं, साथ में वह उन 45 सीटों की दावेदारी भी कर रहे हैं।

कांग्रेस के सहप्रभारी ने चुनावी तैयारियों में जुटने कार्यकर्ताओं को किया आव्हान

धमतरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहप्रभारी सप्तगिरिशंकर उल्का ने तीनों विधानसभा के वरिष्ट नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों में जुड़ने का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सहप्रभारी सप्तगिरि शंकर उल्का धमतरी प्रवास पर पहुंचे यहां धमतरी आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना सहित वरिष्ट नेताओ की उपस्थिति में उनका आत्मीय स्वागत किया गया।

स्वागत सत्कार के पश्चात श्री उल्का ने जिले भर से पहुंचे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही हैं सरकार के कामकाज से सभी वर्ग खुश है क्षेत्र में पिछले साढे 4 सालों में चहुमुखी विकास कार्य कराए गए हैं सरकार की योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिला है उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बूथ स्तर पर राज्य सरकार के कार्यों को बताने की जरूरत है आज हर वर्ग के विकास के लिए भुपेश

सरकार में योजनाएं बनाई है किसानों के लिए भी सरकार ने दर्जनों हितेषी फैसले लिए हैं इसकी बदौलत राज्य में लगातार तेजी से खेती-किसानी में नया आधुनिक बदलाव आ रहा है. इस दौरान अन्य वरिष्ठ नेताओं में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उत्साहित किया।

इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सह प्रभारी सप्तगिरीशंकर उल्का, जिला कांग्रेस कमेटी संगठन प्रभारी बिरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना, उपाध्यक्ष मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण लक्ष्मी ध्रुव, दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, दुग्ध महासंघ अध्यक्ष विपिन साहू, महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, अंबिका मरकाम, लेखराम साहू, अनुसूचित जनजाति आयोग उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, सभापति नगर निगम अनुराग मसीह, जनपद अध्यक्ष कुरूद शारदा साहू, छाया विधायक कुरूद लक्ष्मी कांत साहू मंडी अध्यक्ष कुरूद नीलम चन्द्राकर, मंडी अध्यक्ष धमतरी ओंकार साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष कुरूद तपन चन्द्राकर, सदस्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड मदन मोहन खंडेलवाल, सदस्य मदरसा बोर्ड अशरफ रोकडिया, सदस्य कृषि कल्याण बोर्ड शशि गौर, अध्यक्षगण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घनश्याम साहू, आकाश गोलछा, ईश्वर देवांगन, कैलाश प्रजापति, मुकेश कोसरे, भूषण साहू, डीहूराम साहू, आशीष शर्मा, अखिलेश दुबे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा, अरविंद दोषी, हरमिंदर छाबड़ा, विजय प्रकाश जैन, पंकज महावर, सूर्याराव पवार, लखनलाल ध्रुव, आनंद पवार, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभातराव मेघवाले, प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा मरकाम, महिला कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष घामेश्वरी साहू, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सूर्यप्रभा चेटियार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सोनवानी, जिला उपाध्यक्ष भरत नहार, हेमंत साहू, मनोज साहू, बिशहत राम साहू, जिला महामंत्री आलोक जाधव, अमरदीप साहू, प्रमोद साहू, राजेश साहू, तनवीर कुरेशी, प्रकाश पवार, संतोष सिन्हा, अनिता ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य तारिणी चंद्राकर, सुमन साहू, कुशमलता साहू, मनोज साक्षी, गोविंद साहू मीना बंजारे, कांति कंवर, गुंजा साहू, राजेश ठाकुर, राजेश पांडे, ममता शर्मा, कमलेश सोनकर, सूरज गहरवार, गजेंद्र कुंभकार, संतोषी निषाद, विक्रांत शर्मा, विक्रांत पवार, विशाल शर्मा, सोभीराम नेताम, सविता सोन, मनोज अग्रवाल, विनोद साहू, सेवक तारक, योगेश चंद्राकर, गिरीश साहू, विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष हितेश गंगवीर, नीलमणी साहू, ओम प्रकाश सेन, राजेंद्र भारद्वाज, हरीश चंद्राकर, हरीशचंद्र साहू, रामखिलावन साहू, संतोष हिरवानी, परसराम ध्रुव, गोकुल साहू, अर्जुनराम साहू, मोहित देवांगन, अशोक देवांगन, भोलानाथ देवांगन, उदित साहू, गौतम वाधवानी, तोगु गुरूपंच, विशु देवांगन, अमित वाल्मीकि, देवव्रत साहू, डुमेश साहू, बिंदा नेताम, मानिक साहू, संजय प्रकाश चौधरी, त्रिवेणी साहू, ईश्वरी तारक, अनुपमा साहू, अर्जुन सिंह ओझा, मानसिंह ध्रुव, सन्तोष ध्रुव, रामप्रसाद मरकाम, वतांजली गोस्वामी, अजय सिन्हा, राजेश देवांगन, गंगाराम देशलहरा, आशुतोष खरे, कोमल प्रजापति, रामनाथ यादव, कुलदीप साहू, रवि ठाकुर, सन्नी मरकाम, किशन गजेंद्र, सुंदरलाल प्रजापति, रामचंद्र देवांगन, रितेश कुमार कुलदीप, नवीन गजेंद्र, राजा बंजारे, राकेश मौर्य, टिकेश्वरी मारकंडे, उत्तम साहू, अम्बर चन्द्राकर, पवन यादव सबीना अंजुम, गनेस्वरी कामडे, तिलक सोनकर, हेमंत देवांगन, रवि निर्वाण, मनोज अग्रवाल, काजल बंजारे, मनोज भतपहरी, तुलसी साहू, प्रहलाद साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बरसात के मौसम में स्कूली छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर पार कर रहे रपटा

एमसीबी। सरकार द्वारा गांव-गांव में स्कूल और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ताकि ग्रामीण इलाकों को सड़क से जोड़कर उनका विकास किया जा सके और गांवों में स्कूल बनाकर वहां के बच्चों को शिक्षित किया जा सके, लेकिन मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चनवारीडांड में कुछ और ही मामला देखने को मिला है। यहां पर स्कूल पढ़ने वाले बच्चों,आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए बरसात के समय जान जोखिम में डालकर रपटा पार करना पड़ता है क्योंकि बारिश के दिनों में रपटा जलमग्न हो जाता है और पानी इस रपटा के ऊपर से बहने लगता है। ज्ञात हो कि यह रपटा लोको रेलवे कॉलोनी और ग्राम पंचायत चनवारीडांड को आपस में जोड़ने का काम करता है।ग्राम पंचायत चनवारीडांड कार्यालय और बौरीडांड जाने के लिए यह एक शॉर्टकट रास्ता है इसलिए इस रास्ते का उपयोग नागरिकों द्वारा ज्यादा मात्रा में किया जाता है।रपटा के इस पार रेलवे कॉलोनी में रहने वाले छात्र छात्राएं रपटा के उस पार स्थित स्कूल में अध्ययनरत हैं। जिन्हें बरसात के समय में जान जोखिम में डालना पड़ रहा है।पंचायत द्वारा जो रपटा बनाया गया है,वह भी इतना घटिया निर्माण किया गया कि वर्तमान में यह रपटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।जिससे निकलने में अनहोनी का डर हमेशा सताता रहता है। रपटा को क्रॉस करने वाला दूसरा रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते से जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा।इसलिए स्कूल के बच्चे एवं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन और बारिश के समय इस को पार करते हैं। अब ऐसे में पंचायत द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे ताकि स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता मिल सके। पंचायतों में लाखों रुपए का आवंटन होता है। इसके बावजूद भी गांव के विकास के लिए पंचायत कोई कार्य करने पर ध्यान नहीं देती हैं।जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है।

वहीं छात्रों का कहना है कि टूटे हुए रपटा से निकलते समय डर लगता है। कई बार हम स्कूल जाते समय गिर कर घायल भी हो चुके हैं,और तो और बारिश के मौसम में तो हम लोग स्कूल बड़ी ही मुश्किल से जा पाते हैं क्योंकि रपटा पर ज़्यादा पानी आ जाता है।स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन खतरों का सामना करते हुए रपटा के ऊपर से बहते हुए पानी में से निकलना पड़ता है। कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। लेकिन ज़िम्मेदार अधिकारी ध्यान नही दे रहे हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत चनवारीडांड की सरपंच गौरी सिंह ने बताया कि पंचायत द्वारा इस रपटा का निर्माण लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व करवाया गया था। बरसात के दिनों में स्कूली छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उनके द्वारा विधायक से इस बाबत मौखिक चर्चा कर मांग की गई थी तथा पंचायत इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

राजीव युवा मितान शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना एक मात्र उद्देश्य : श्याम

कोरबा। कोरबा जिलान्तर्गत करतला ब्लॉक राजीव युवा मितान की समीक्षा बैठक करतला जनपद पंचायत सभागार मे राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक श्याम नारायण सोनी की अध्यक्षता रखी गई थी, जिसमें करतला ब्लाक के 78 पंचायत क्लब के पदाधिकारी वह सदस्य शामिल हुए।

इस अवसर पर श्याम नारायण सोनी ने क्लब के सभी पदाधिकारियों से पिछले साल होने वाले कार्यक्रम की जानकारी ली साथ ही आगामी कार्यक्रम कैसे हो, कैसे किया जाए उस पर विस्तृत चर्चा की, श्री सोनी ने कहा कि प्रदेश मे मुख्यमंत्री ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर, गांव-गांव मे लोगों की बीच जाने वह जुड़ाव का एक अच्छा माध्यम साबित हुआ हैं, उन्होंने ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मुल भावना को जिस प्रकार से संरक्षण करने वह उभारने का प्रयास हुआ हैं, वह अपने आप मे अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ की समूल योजनाओं को कैसे जन-जन तक पहुंचा, इस पर लगातार हमे कार्य करना हैं, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके।

इस अवसर पर रामपुर विधानसभा महिला समन्वयक धनेशवरी कंवर ने क्लब के सदस्यों द्वार किए कार्यो की बारी-बारी से समीक्षा की साथ ही उन्होंने कहा कि हमे गर्व होना चाहिए कि हम सब राजीव युवा मितान के महती योजना के हिस्सा हैं और हमे अपने संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी मिली हैं, निश्चित ही शासन गरीब, किसान, मज़दूर, वह बेरोजगारों के उत्थान के लिए नए-नए कार्ययोजना ला रही है जिसे जनता तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना हैं। इस अवसर पर राजीव युवा मितान क्लब की महिला जिला समन्वयक नफीसा बेगम, रामपुर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष शिवम राय, आशुतोष वर्मा, अमन अग्रवाल, महेश मैत्री, रजनीकांत पटेल, समेत क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने पढ़ाई पूरी कराने वाले पति का साथ छोड़ा

■ पति ने शिक्षिका पत्नी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की

कोरबा। छत्तीसगढ़ कोरबा कोरबा जिले में भी एसडीएम ज्योति मौर्या जैसे बेवफाई की कहानी सामने आ रही है। कोरबा जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे एक मजदूर पति ने अपनी बेवफा पत्नी पर उचित कार्यवाही की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचा।

उसने बताया कि मैं शांति कुमार कश्यप, पिता रघुनाथ प्रसाद कश्यप, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बालको नगर तह व जिला कोरबा छ.ग. का है, तथा जो कि मेरा विवाह दिनांक 06/05/2011 को शिक्षिका पत्नी उम्र 34 वर्ष के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था जो कि इस दौरान हमारी दोनों के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्री का जन्म हुआ।

यह कि मैं अपनी पत्नी को आगे की पढाई करवाया और शिक्षा कर्मी तृतीय वर्ग में नौकरी भी दौड़ धूप कर मैं अपने परिश्रम से नौकरी भी लगवा दिया, लेकिन उसका 02 वर्षों से किसी गैर पुरुष के साथ संबंध है मैं अपने ससुराल वालों को बताया कि आपकी बेटी गलत रास्ते में जा रही है और बल्कि उसके मायके वाले अपनी बेटी को समझाने के बजाये उसे मेरे प्रति और भड़का दिया और गलत निर्देश दिया गया एवं बढ़ावा तथा सहयोग दिया गया। मेरी पत्नी शिक्षिका को अहकार व लालच में आकर अपने माता-पिता, भाई बहन के अनुसार

उसके निर्देश पर चलने लगी। मेरी पत्नी मेरा अंकसूची, आधार कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री पेपर व अन्य दस्तावेज व सोना-चांदी व अन्य सामान को भी लेकर चली गयी है। वर्तमान में मेरी पत्नी शिक्षिका जो कि एक शा. प्रा. स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ है तथा उसका विकासखण्ड कोरबा है, अब वह जीवित पति के रहते हुए व बिना तलाक हुए गैर पुरुष के साथ शारीकिर संबंध बनाकर 03 तृतीय, बच्चा प्राप्त कर लिया गया है एवं परिवार परामर्श केन्द्र में झूठा बयान दिया गया। बालको थाना में झूठा एफ आई.आर. किया गया। जिला सत्र न्यायालय कोरबा में झूठा बयान दिया एवं अपने पति को झूठा आरोप लगाया गया एवं पूरे परिवार एवं समाज में बदनाम किया गया। पति ने शिक्षिका पत्नी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सर्व आदिवासी समाज ने किया यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन

कोरिया। कोरिया में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। साथ ही राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल, पहली बार छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया। ये विरोध कोरिया जिले में किया गया। यहां सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अधिक संख्या में सभी आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए और पुराने आरटीओ कार्यालय के पास से रैली निकाल कर सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सभी ने यूसीसी का विरोध करते हुए नारे लगाए। सर्वआदिवासी समाज का कहना है कि देश भर 705 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। ये प्राचीन समय से अपनी सुविधानुसार जीवन यापन कर रहे हैं। देश के संविधान ने इन्हें मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया है। ऐसे में देश के 15 करोड़ आदिवासी कहीं न कहीं यूसीसी से खुद को अलग रखना चाहते हैं।

भाजपा शासनकाल के दो साल का बोनस किसानों ने मांगा

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने कई बार शासन से गुहार लगाई है। लेकिन किसानों की परेशानी दूर नहीं हुई। एक बार फिर भारतीय किसान संघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों अपनी 15 सूत्रीय मांगों में कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाया है। जिसमें ये कहा गया था कि, सरकार बनते ही बीजेपी शासन के दो साल का बोनस किसानों को दिया जाएगा।पूरे प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी। लेकिन ना तो बोनस दिया गया और ना ही शराबबंदी हुई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसानों का वादा पूरा करने के आश्वासन के बाद ही सत्ता में लौटी है। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने पुराने वादों के साथ नई मांगों को सरकार के सामने रखा है।विधानसभा चुनाव के दौरान ये मांगें किसान संघ मनवाना चाहता है।वहीं शासन भी चाहता है कि किसानों को किसी भी बात की परेशानी ना हो।

मितानिनों ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार

कोरबा। राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में

सहयोग प्रदान करने वाली मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण निधि योजना अंतर्गत राशि में 01 अप्रेल 2023 से मानदेय में 2200 (दो हजार दो सौ) रूपए की वृद्धि पर जिले के मितानिनों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। पूर्व विधायक श्री श्याम लाल कंवर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मितानिनों ने कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं जिला पंचायत सीईओ से भेंट कर अपनी खुशी प्रकट की। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि मितानिनों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती है। मितानिनों के योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है।

यूसीसी का विरोध, आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन

धमतरी। केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिकता कानून का अब विरोध शुरू हो गया है। धमतरी में युनिफार्म सिविल कोड को लेकर धमतरी में सर्व आदिवासी समाज ने आपत्ति जताते हुए इसे रदद करने की मांग की है। आदिवासी समाज ने इस मामले में राष्ट्रपति,विधि आयोग,प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वही इस बिल के विरोध में समर्थन देने मुस्लिम, सतनामी, बौद्ध, महार समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष जीवराखन लाल मरई का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से जनजाति समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत देश में सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जायेगा। आदिवासियों की रीतिरिवाजो को कमजोर कर देगी,जिन्हें कानून का बल दिया गया है। ऐसे में कॉमन सिविल कोड बिल भारत देश में न लागू किया जाए। कार्यकारी जिलाध्यक्ष महेश रावटे ने बताया कि भारत विविधता का देश है भारतीय नागरिक विभिन्न धर्मो समुदायों जातियों और जनजातियों से आते है।

महापौर ने रवाना किया पौधा तुंहर द्वार वाहन को

कोरबा। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2023 में वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन हेतु वृहद स्तर पर इस वर्ष पूरे राज्य में करीब 03 करोड़ औषधि, फलदार व छायादार पौधों का रोपण एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री की पूरे प्रदेश हेतु मंशा के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत अधिक से अधिक औषधि, फलदार व छायादार पौधों को पौधारोपण हेतु प्राथमिकता से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के उपरोक्त लक्ष्य को ध्यान में रखकर नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित परिसर में आज महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्यामसुंदर सोनी, आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय व कोरबा डी.एफओ. श्री पी.अरविंद ने निःशुल्क पौधा वितरण 2023 के तहत 'पौधा तुंहर द्वार' वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। साथ ही महापौर, सभापति व निगम आयुक्त ने साकेत भवन में आए हुए हितग्राहियों को विभिन्न प्रजातियों के औषधि पौधें, छायादार पौधें व अन्य प्रकार के पौधों का निःशुल्क वितरण किया।

गृहमंत्री ने बेरला में भक्त माता कर्मा चौक व प्रतिमा का किया लोकार्पण

बेमेतरा। लोक निर्माण, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने विकासखंड मुख्यालय बेरला में भक्त माता कर्मा चौक व भक्त माता कर्मा की प्रतिमा लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक श्री आशीष कुमार छाबड़ा, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री थानेश्वर साहू, अध्यक्ष जिला केन्द्रीय बैंक दुर्ग श्री राजेन्द्र साहू, अध्यक्ष साहू समाज बेरला श्री सूर्यकांत साहू, उपध्यक्ष भारत भूषण साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत श्री राशबिहारी कुर्रे सहित जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, पार्षदगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

साहू ने कहा कि हम सब को माता कर्मा के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होने जिस प्रकार त्याग को अपनाया ठीक उसी प्रकार समाज के तत्वाधान में हमें भी मां कर्मा माता की तरह आने वाली प्रत्येक त्याग को अपनाकर आगे बढना है।

कार्यक्रम में गृहमंत्री ने समाज के लोगों को साथ लेकर आगे बढने की बात कही और कहा माता कर्मा हमारे समाज की आराध्य देवी है, माता ने त्याग और तपस्या की जो राह समाज को दिखाई है हमें उसी राह पर चलने की अपील की है।

गृहमंत्री श्री साहू ने सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकारी की उपलब्धियाँ गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है।जिससे हर वर्ग के पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। बेमेतरा जिले में भी इन चार सालों में बहुत विकास हुआ है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इस राशि का उपयोग वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों आदि में कर रहे है। इससे उनके परिवार में आर्थिक बोझ कम हुआ है, यह हम नहीं स्वयं लाभान्वित हितग्राहियों ने कहा है। इस तरह की तमाम योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि साहू समाज का भी राज्य और सामाजिक विकास में योगदान है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने समाज की संस्कृति व परंपराओं को अच्छे से संजोकर रखा है। आप लोगों द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे है। इससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि सामाजिक प्रगति के लिए आपसी समन्वय एकता और विचारों का सकारात्मक होना अति आवश्यक है और सकारात्मक विचार शिक्षा ही दे सकती है। इसके लिए हम सभी को सामाजिक तरक्की हेतु शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए।

फर्जी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, दोगुना मुनाफे का झांसा देकर की ठगी

बिलासपुर। मंगलवार को बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को डबल मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने मंगला दीनदयाल कॉलोनी में दबिश देकर फर्जी डायरेक्टर अब्दुल जाकिर जिलानी को गिरफ्तार कर लिया।

सिविल लाइन पुलिस के अनुसार, मंगला के दीनदयाल कॉलोनी निवासी अब्दुल जाकिर जिलानी 45 वर्ष ने कुद को एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बताया। उसने रतनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले किरण कुमार कश्यप और अन्य लोगों को कंपनी में पैसा लगाने पर डबल मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपी ने प्रार्थी के अलावा अन्य लोगों से करीब 53 लाख रुपए रकम डबल करने के नाम पर लिया। जो तय समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं किया गया।

आरोपी ने अपने आप को कथित डिस्टर्ब मनी कमोडिटीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताकर लोगों को झांसे में लिया था। जिसके बाद उसने कई लोगों से रूपये ले लिया था। जिसके बाद वह कार्यालय बंद कर भाग गया।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी अब्दुल जाकिर जिलानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरु कर फर्जी डायरेक्टर की तलाश शुरु की। मुखबिर से सूचना मिलने पर मंगलवार देर रात को पुलिस ने मंगला दीनदयाल कॉलोनी में दबिश दी। जहां से फर्जी कंपनी के डायरेक्टर अब्दुल जाकिर जिलानी को पकड़कर उसे न्यायालय में पेश किया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल को सजा दिलाने वाले पूर्णेश ने किया सुको का रुख

नईदिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर मांग की है कि अगर कांग्रेस नेता मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, पूर्णेश मोदी ने उसी दिन अपने वकील पीएस सुधीर के माध्यम से शीर्ष अदालत में कैविएट दायर की। निचली अदालत के आदेश या फैसले को चुनौती देने वाले किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील पर कोई आदेश पारित होने पर सुनवाई का अवसर मांगने वाले वादी द्वारा अपीलीय अदालत में एक कैविएट दायर की जाती है।

भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

नईदिल्ली। 24 जुलाई को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा ने आज 3 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने गुजरात से बाबूभाई जेसंगभाई देसाई और केसरीदेव सिंह चाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल से अनंत महाराज को टिकट दिया है। अनंत महाराज के नाम ने सबको चौंकाया है। हालांकि जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने उनके साथ बैठक की थी, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी। बंगाल की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होंगे। 5 पर टीएमसी और एक पर भाजपा की जीत मानी जा रही है।

ममता ने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया : रविशंकर

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद बंगाल पहुंचने के साथ ही उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी के लोकतांत्रिक साख की अभी परीक्षा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ममता चारों सांसदों को पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की इजाजत देंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की लेकिन राज्य भर में हिंसा की शायद ही कोई घटना हुई। तो फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों है? कल भी वोटों की गिनती के दौरान किसी की हत्या हो गई थी। निर्वाचित उम्मीदवारों से कहा गया कि वे टीएमसी में शामिल हों अन्यथा उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। ममता जी, आपने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है।

राहुल की अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस का मौन सत्याग्रह

नईदिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में बुधवार को मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर राज्य की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह किया। पार्टी महासचिव संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सबसे मजबूत और मुखर प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें पीएम मोदी और अदानी समूह के बीच संबंधों का खुलासा किया गया। कांग्रेस मौन विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बात आज एक व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और लोकतंत्र के अंदर न्याय होना चाहिए और खुलेपन से बात करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्था को कमजोर किया जा रहा है ये हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

महाराष्ट्र की छवि खराब कर रहे हैं फडणवीस : संजय राउत

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल लगातार जारी है। जब से अजित पवार शिंदे और फडणवीस की सरकार में शामिल हुए हैं, तब से राजनीति और तेज हो गए हैं। इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने फडणवीस पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान सरकार में बहुत सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्र की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने तक हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे था। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार में काफी बढ़ोतरी हुई है। अजित पवार और छगन भुजबल को देखिए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट नेताओं से भरी है। देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

विपक्षी एकता के संयोजक पद पर नीतीश के सामने चुनौती

■ लालू-शरद नहीं, सोनिया होंगी सामने

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का एलान करने के लिए 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। इस बैठक में देशभर से 15 दल जुटे थे, हालांकि आम आदमी पार्टी ने बगैर घोषणा किए पैर खींच लिए थे। मीडिया के सामने 14 दल ही आए थे। अब बेंगलुरू में दो दर्जन दलों का इससे भी बड़ा जुटान हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे कितने खुश हो रहे होंगे, यह उनका मन ही जानता है। क्योंकि, खबर अब बेंगलुरू में विपक्षी एकता के लिए हो रही बैठक का संयोजन करने वाली कांग्रेस पार्टी से है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की संयोजक और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी।

नीतीश-लालू के अलावा जदयू-राजद से यह भी जाएंगे

जनता दल यूनाईटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेंगलुरू की बैठक के लिए बुलावा आ चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी नीतीश के साथ जाएंगे। जदयू से और एक मंत्री का नाम संभव है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम पक्का हो चुका है। पार्टी की तरफ से एक और नेता जाएंगे और ज्यादा संभावना मनोज झा के नाम की है। 23 जून को पटना में हुई बैठक का संयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, हालांकि कई नेताओं को पटना बुला लाने में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अहम भूमिका रही थी।

सोनिया के कारण क्या-क्या होगा, समझ रहा जदयू

पटना में हुई बैठक में फैसला हुआ था कि अगली बैठक का संयोजन कांग्रेस करेगी। पटना में हुई बैठक के दौरान कई नेताओं ने इस बैठक के आयोजन के लिए नीतीश कुमार को बधाई के साथ धन्यवाद दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के संयोजक' शब्द का इस्तेमाल भी किया, हालांकि उम्मीद से उलट इस बैठक के बाद मीडिया के सामने संयोजक पद पर नाम को लेकर घोषणा नहीं की गई। नीतीश इस नाम के हकदार थे।

लेकिन, घोषणा नहीं हुई। तभी यह आशंका थी कि अगली बैठक में कुछ तो होगा। क्या होगा, इसकी भनक अब बिहार पहुंच गई है। भाजपा के खिलाफ चल रहे मौजूदा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी भी कांग्रेस के संयोजन से बेंगलुरू में प्रस्तावित बैठक में शामिल हो रही हैं। सोनिया पहले से भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन की चेयरपर्सन हैं। पटना आने में राहुल गांधी हिचकिचा रहे थे, लेकिन बेंगलुरू में सोनिया रहेंगी तो क्या होगा, जदयू को अंदाजा है।

किसके पक्ष में क्या अच्छी बात, समझना होगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास ही उन्होंने शुरू किया। 12 जून को बैठक बुलाने पर कांग्रेस ने उदासीनता दिखाई तो उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मदद से 23 जून को मजबूती के साथ विपक्षी एकता की बैठक कर ली। इस बैठक में संयोजक की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बीच में लालू-नीतीश ही थे। भ्रष्टाचार के नाम पर लालू के लिए अभिभावक या संरक्षक की भूमिका तो हो सकती है, लेकिन सक्रिय संयोजक के रूप में नहीं। शरद पवार की भूमिका भी ऐसी हो सकती है। अब बेंगलुरू में आ रहीं सोनिया की बात करें तो उनकी दावेदारी मजबूत होने का कारण तीन हैं- पहला यह कि सोनिया मौजूदा ऐसे ही गठबंधन की अध्यक्ष हैं, दूसरा यह कि राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में उनके पास और कोई पद नहीं है और तीसरा यह कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकताके गठबंधन का अस्तित्व नहीं हो सकता है।

विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस को धुरी बनाएंगी सोनिया गांधी, 24 पार्टियों के लिए रखेंगी रात्रिभोज

नई दिल्ली। पटना के बाद अब बेंगलुरू में 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक होगी। इस बैठक में कुल 25 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को सोनिया गांधी पार्टी के सभी नेताओं को रात्रिभोज पर आमंत्रित कर सकती हैं। वहीं, बैठक में एक नया दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल होगा। इसके अलावा, बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। इससे पहले कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी यही दावा किया था। गौरतलब है, पटना में हुई बैठक में करीब 17 दलों ने हिस्सा लिया था। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के लिए आठ नई पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है।

यह है नई पार्टी- मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), कोंगु देसा मक्कल काची (केडीएमके), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (मणि) के 17 जुलाई को बैठक में शामिल होने की संभावना है।

2014 से 2024 तक बदला समीकरण- सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई पार्टियों में से केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सहयोगी थे। वहीं, 23 जून को पटना में हुई बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, शरद पवार समेत अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर पार्टी का समर्थन नहीं करती है तो वह विपक्षी एकता से अलग हो जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा भारत के लिए अहम

आज से दो दिवसीय फ्रांस दौरे पर रहेंगे, 15 को जाएंगे यूएई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस दौरे पर रहेंगे। 14 जुलाई को होने वाले फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड समारोह में के पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं। दो दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट (राफेल एम) और तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देश आगे आ सकते हैं।

पीएम गुरुवार को ला सीन म्यूजिकल में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन एलिसी पैलेस में अपने आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के द्विपक्षीय वार्ता करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसी दिन दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा होगी। मैक्रॉन लौवर संग्रहालय के कौर मार्ली प्रांगण में पीएम के लिए एक औपचारिक डिनर होस्ट करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पीएम मोदी को प्रसिद्ध संग्रहालय के दौरे पर भी ले जाएंगे। यहां दोनों नेता लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। इसके बाद मोदी और मैक्रॉन लौवर संग्रहालय की छत से एफिल टॉवर पर आतिशबाजी का आनंद लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ शीर्ष भारतीय सीईओ का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

इस दौरे से भारत को क्या उम्मीदें हैं?

पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट (राफेल एम) खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले रक्षा बलों द्वारा यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे गए थे। प्रस्तावों के अनुसार, भारतीय नौसेना को चार प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल एम मिलेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर पुराने मिग-29 के स्थान पर इन लड़ाकू विमानों को तैनात करेगी। राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस द्वारा बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है। जैसा 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के दौरान किया गया था। इन प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में पहले ही उच्च-स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष इसे रखा जा सकता है। इसके साथ ही फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है। मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड (एमडीएल) में तीन और स्कॉर्पीन (कालवेरी) श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक किलर-हंटर पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद 15 जुलाई को अबु-धाबी के लिए उड़ान भरेंगे। इस दौरान वह अबू धाबी के शासक और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी

नईदिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का बहुचर्चित मैच श्रीलंका में होगा क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी । आईपीएल चेयरमैन अरूण धूमल ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। धूमल इस समय डरबन में आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की बैठक के लिए गए हैं । उन्होंने पुष्टि की कि बीसीसीआई सचिव जय शाह और पीसीबी प्रमुख जाका अशरफ की गुरुवार को होने वाली आईसीसी बोर्ड की बैठक से पहले मुलाकात हुई ताकि एशिया कप का कार्यक्रम तय हो सके ।

धूमल ने कहा ,''हमारे सचिव ने पीसीबी प्रमुख जाका अशरफ से मुलाकात की और एशिया कप 2023 के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया । यह उसी के अनुरूप है जिस पर पहले बात की गई थी । पाकिस्तान में लीग चरण के चार मैच होंगे जिसके बाद नौ मैच श्रीलंका में होंगे ।इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच शामिल है । दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं तो वह भी श्रीलंका में होगा ।'' उन्होंने पाकिस्तान मीडिया में आ रही इन अटकलों को खारिज किया कि भारतीय टीम पाकिस्तान जायेगी । पाकिस्तान के खेल मंत्री अहसान मजारी के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थीं । धूमल ने कहा ,'' इस तरह की कोई बात नहीं हुई । भारतीय टीम या हमारे सचिव पाकिस्तान नहीं जायेंगे । सिर्फ कार्यक्रम तय किया गया है ।''

भारतीय टीम श्रीलंका के दाम्बुला में पाकिस्तान से खेल सकती है । पाकिस्तान का अपनी धरती पर एकमात्र घरेलू मैच नेपाल के खिलाफ होगा । इनके अलावा पाकिस्तान में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश, बांग्लादेश बनाम श्रीलंका और श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच होंगे ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 224 अंक टूटा निफ्टी 19,400 के नीचे

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार नरम रहे क्योंकि निवेशकों ने भारत और अमेरिका में आज आने वाले प्रमुख सीपीआई महंगाई के डेटा से पहले सावधानी बरती। आज के कारोबार में सेंसेक्स 224 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 55 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले विदेशी निवेशकों की लिवाली जारी रहने और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी के चलते शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 223.94 अंक यानी 0.34 फीसदी टूटकर 65,393.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,811.64 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,320.25 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55.10 अंक यानी 0.28 फीसदी गिरा। निफ्टी दिन के अंत में 19,384.30 अंक पर बंद हुआ।

विप्रो तीन साल में एआई में 1 अरब डॉलर का करेगी निवेश

नईदिल्ली। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि वह अगले तीन सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी कि निवेश एआई, बड़े डेटा और एनालिटिक्स समाधानों के विस्तार के साथ-साथ नई रिसर्च और प्लेटफॉर्म के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। दुनिया भर की कंपनियों, बैंकों से लेकर बड़ी तकनीक तक, ने चैटजीपीटी के बाद एआई में निवेश दोगुना कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एआई चैटबॉट ने 2022 के अंत में दुनिया में तूफान ला दिया। कंपनी ने अपने पहला एआई इनोवेशन इकोसिस्टम विप्रो एआई360 को भी लॉन्च किया और कहा कि वह अगले 12 महीनों के दौरान अपने सभी लगभग 250,000 कर्मचारियों को एआई पर प्रशिक्षित करेगी।

ऑनलाइन गेमिंग पर लगा 28 फीसदी जीएसटी

नईदिल्ली। जीएसटी से जुड़े मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद ने मंगलवार, 11 जुलाई को अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ स्पर्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया। जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का दर्द छलक पड़ा। उनका मनाना है कि सरकार के इस निर्णय से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की हत्या हो जाएगी। सरकार के इस फैसले पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने काफी ऐतराज जताय है। नजारा टेक का कहना है कि 28 फीसदी की दर से टैक्स लगने के कारण इसके रेवेन्यू पर मामूली फर्क पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि यह टैक्स केवल उसके कौशल-आधारित रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर लागू होगा। वित्त वर्ष 2023 के डेटा के अनुसार इस सेगमेंट की नजारा टेक के रेवेन्यू में केवल 5.2 फीसदी की हिस्सेदारी है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में 2% बढ़ी : सियाम

नईदिल्ली। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर दो प्रतिशत बढ़कर 3,27,497 इकाई हो गई। उद्योग निकाय सियाम ने बुधवार को यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में डीलरों को 3,20,985 यात्री वाहन भेजे गए थे। सियाम ने कहा कि पिछले महीने दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री दो प्रतिशत बढ़कर 13,30,826 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 13,08,764 इकाई थी। बयान के मुताबिक समीक्षाधीन माह में तिपहिया वाहनों की कुल बिक्री लगभग दो गुना बढ़कर 53,019 इकाई हो गई, जबकि जून 2022 में यह 26,701 इकाई थी।

चीन से आगे निकलने का मतलब केंद्र की आर्थिक नीतियां सही दिशा में

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

केंद्र में कार्य करते हुए मोदी सरकार को नौ साल पूरे हो चुके हैं । इस कार्यकाल की अलग-अलग दृष्टि से समीक्षा भी हो रही है। आर्थिक क्षेत्र भी इसका एक अहम हिस्सा है। देखा जाए तो पिछले कार्यकाल समेत इस कार्यकाल में सतत बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। वस्तुत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के संयुक्त प्रयास ही नहीं सभी केंद्रीय विभागों के मंत्रियों का परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा अंतर लिए हुए नहीं दिखता। हर विभाग का आर्थिक मोर्चे पर मिलजुल कर नीतियां बनाने का प्रयास ही है जो दुनिया भर के निवेशकों को भारत यह भरोसा दिलाने में सफल रहा कि आपना एक रुपया भी भारत के लिए मायने रखता है, वह यहां पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए दुनिया में कहीं निवेश करना है तो वह देश भारत है। आर्थिक दृष्टि से की जानी वाली ग्रोथ, नए रोजगार के अवसर के लिए आपका भारत में स्वागत है ।

निश्चित ही भारत के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पैदा किए गए भरोसे का ही यह परिणाम है जो आज भारत में गति लिए विदेशी निवेश आ रहा है । बड़े-बड़े उद्योग यहां स्थापित किए जा रहे हैं । दुनिया के देशों का भारत के प्रति भरोसा इतना कि अब सर्वे भी इसकी गवाही दे रहे हैं। इस संदर्भ में वस्तुत: हाल ही में आया एक सर्वे यह बता रहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी उड़ान को अब रोका जाना संभव नहीं। यह रिपोर्ट हम सब भारत वासियों को उत्साह से भर देती है। वहीं, जो लोग देश में महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसे अन्य विषयों को उठाते आए हैं, ऐसा नहीं है कि यह तमाम समस्याएं आज भारत के लिए चुनौती नहीं

रहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को अभी विकासशील और अभी से आगे अत्यधिक सुखद, समृद्ध देश बनने के लिए लम्बी यात्रा तय करनी है, किंतु इसके साथ समझने वाली बात यह है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जो अच्छा हो रहा है उसका हमें राजनीति से ऊपर उठकर स्वागत करना चाहिए।

निवेश के मामले में सबसे आकर्षक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में जब चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर में पसरा है जबकि भारत का एरिया 33 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम है। स्वभाविक है कि क्षेत्रफल की दोगुनी से ज्यादा अधिकता होने के कारण से चीन के पास प्राकृतिक संसाधन भारत से अधिक हैं, इसलिए हम देखते भी हैं तमाम प्रकार के कच्चे माल के लिए दुनिया के कई देश चीन पर निर्भर रहते आए हैं। फिर भारत और चीन की स्वतंत्रता में भी बहुत अधिक अंतर नहीं। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद चीन को पूरी तरह स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया था। किंतु 1945 में स्वतंत्रता के बाद माओ त्से तुंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट्स और नेशनलिस्ट्स के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद अगले चार साल तक यहां सिविल वॉर की स्थिति बनी रही।

वर्ष 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई। तब चीन पुराने कोमिंगतांग सरकार के कुशासन से मुक्त हुआ। तब से लेकर आज तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या होने के बाद भी आर्थिक मोर्चे पर यह देश दुनिया के विकसित देशों को टक्कर देता आया है। वहीं, भारत चीन से दो वर्ष पूर्व स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत के पास कोई स्पष्ट आर्थिक रीति-नीति नजर नहीं आई थी। शुरू में भारत इसी में उलझा रहा कि वह रूस और चीन से पोषित साम्यवादी-समाजवादी सिद्धांतों पर चलेगा अथवा अमेरिका-इंग्लैण्ड के पूंजीवादी सिद्धांत पर या फिर अपने परंपरागत प्राचीन सिद्धांतों को नए संदर्भों के साथ अपने लिए स्वीकार करेगा। स्वभाविक है इस ऊहापोह में कई वर्ष निकल जाने थे, सो हुआ भी। इस बीच भारत में कई सरकारें आईं और गईं। हालांकि विकास में सभी का अपना कुछ न कुछ योगदान है, किंतु जो कार्य मोदी कार्यकाल के दौरान पिछले नौ सालों में हुआ है, वह हर मायने के काबिले-तारीफ है।

बंगाल समस्या का स्थायी समाधान योगी मॉडल

प्रणय विक्रम सिंह

भद्र बंगाल में लोकतंत्र की आत्मा सुबक रही है। 41 से अधिक हत्याओं और सैकड़ों घायलों के साथ रक्तरंजित पंचायत चुनावों से वहां जम्हूरियत का जिस्म फिर से लहूलुहान हो गया है। बूथ के बूथ खून से नहाए हुए हैं। हर वोट पर इंसानी खून की छींटे देखी जा सकती हैं। 'बूथ कैप्चरिंग' से जहां लोकतंत्र जगह-जगह 'बे-लिबास' हुआ तो बेलगाम कत्ल-ओ-गारद से कानून-व्यवस्था की अस्मत तार-तार हुई और देश, दुनिया भर में शर्मसार हुआ। हैरत है, कि यह सब हो रहा है उस भद्र मानुष के बंगाल में जो युवा संन्यासी विवेकानंद की ललकार से जगा है। जो रवींद्र के संगीत में ढला है। जो वैभव, वैराग्य और विकास की त्रिगुटि में पगा है। अब इससे भी बड़ी विडम्बना क्या होगी, जो ममता बनर्जी कभी स्वयं राजनीतिक हिंसा से पीड़ित थीं, वाम जनित हिंसा के सैलाब को पार कर बंगाल शेरनी कहलायी थीं, वही आज इस प्रचण्ड हिंसा की वाहक मानी जा रही हैं। विदित हो कि 10 करोड़ की आबादी, लगभग 5.67 करोड़ मतदाता वाले बंगाल में ग्राम पंचायत की 63229, जिला परिषद की 928 व पंचायत समिति की 9730 सीटों समेत कुल 61636 पोलिंग स्टेशन पर चुनाव हुए हैं। राज्य चुनाव आयोग की मांग पर शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्र से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों को भी समय से भेजा गया था। राज्य के पास अपना 'दक्ष पुलिस बल' तो पहले से ही मौजूद था। फिर क्यों नेताजी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंग भूमि खून से लाल हुई? पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद से ही बंगाल का माहौल हिंसक होने लगा था, उसके बाद भी ममता सरकार की ये अक्षम्य ढिलाई असहज करने वाली है। ध्यान से सुनिए कि पंचायत चुनाव में हुई ये 41 हत्याएं बंगाल में लोकतंत्र के खतरे में होने का संकेत नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या की करुण चीत्कार हैं। 'ममता सरकार' की निर्ममता से बंगाल के दामन पर लगे ये खून के धब्बे भला कैसे धुलेंगे? कुछ राजनीतिक चिंतक मुख्यमंत्री ममता के बचाव में कह रहे हैं कि राज्य बहुत बड़ा है, हर जगह पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। बे-वजह मामले को तूल दिया जा रहा है। हालांकि यह कुतर्क है लेकिन यदि उनकी बात को मान भी लिया जाए तो विचारणीय है कि देश का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। यहां वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में 12.43 करोड़ से अधिक मतदाता और 02 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन थे। लेकिन पूरा चुनाव बगैर बूथ कैप्चरिंग के ही सम्पन्न हो गया था। सारे फैसले बैलेट से हुए, बुलेट चलाने की हिमाकत और हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सका। यही नहीं अभी हाल में नगर निकाय चुनाव में महापौर की 17, निगम पार्षद की 1420, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199, सदस्य की 5327, नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 और सदस्य की 7177 सीटों पर वहां चुनाव सम्पन्न हुए, लेकिन एक भी सीट पर हिंसा की मामूली घटना भी सुनने को नहीं मिली। मतलब बंगाल से ढाई गुना अधिक आबादी वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हिंसा मुक्त चुनाव होता है, एक बार नहीं बार-बार होता है। और मुख्यमंत्री ममता का बंगाल राजनीतिक हिंसा से बार-बार दहक जाता है। वहां चुनाव का मतलब लोकतंत्र का उत्सव नहीं लाशों को ढेर बन गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि घने अंधकार को चीरने के लिए प्रकाश की प्रेरणा होना आवश्यक है। ध्यान से देखें तो, अराजकता और हिंसा के अंधकार में घिरी ममता सरकार के लिए 'योगी मॉडल' प्रकाश की प्रेरणा के समान ही है। इतना कुछ सुनने और देखने के बाद सहज ही एक सवाल जन्म लेता है कि बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है?

लोकसभा चुनाव : भाजपा की तैयारी

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वह सब कुछ ठोक-बजा कर प्रत्याशियों का फैसला करने के लिए जमीन से लेकर बंद कमरों तक में रणनीति बना रही है। टिकट बांटते समय तमाम बातों का ध्यान रखा जायेगा, लेकिन अबकी से प्रत्याशियों का चयन करते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अहम भूमिका रहेगी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी थी। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 2017 के विधान सभा चुनाव मोदी का चेहरा आगे करके जीता था और चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे में न उनसे राय ली गई थी और न ही उन्होंने इसमें दखलंदाजी की थी, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने योगी को आगे करके लड़ा था और उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन पार्टी का रहा था, जिसके बाद पार्टी के भीतर योगी का कद काफी बढ़ गया था, इसी के चलते अबकी से टिकट बंटवारे के समय योगी को आलाकमान अनदेखा नहीं कर पाएगा। खासकर पूर्वांचल में योगी की पसंद नापसंद का ज्यादा ख्याल रखा जा सकता है। यानी उनका सिक्का भी चलेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में पार्टी के भीतर योगी का कद प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर दो का समझा जाने लगा है। वह न केवल दमदार तरीके से सरकार चला रहे हैं, बल्कि कई राज्यों के चुनाव प्रचार में वह पार्टी के लिए तुरूप का इक्का भी साबित हो चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशियों के लिए नामों पर चर्चा शुरू कर दी है। यह चर्चा सार्वजनिक रूप से तो नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर छन कर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि इस बार किस निवर्तमान सांसद का टिकट नहीं देना है। कुछ प्रत्याशी तो उम्रदराज होने के कारण चुनावी रेस से बाहर होते दिख रहें हैं, वहीं कुछ आलाकमान की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यह वह सांसद हैं जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर पार्टी पर आई किसी मुसीबत की घड़ी के समय जनता के बीच इनका प्रभाव काफी कम या नहीं के बराबर देखने को मिला था। इसे उदाहरण से समझा जाए तो जब किसानों ने नये कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया तो भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जबकि आलाकमान चाहता था कि पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेता और सांसद-विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यहां के आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने के लिए मनाएं। इसी प्रकार लखीमपुर-खीरी में भी जब केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने वहां कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, तब भी वहां के स्थानीय सांसद और केन्द्रीय मंत्री टेनी का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना और बयानबाजी काफी घटिया स्तर की रही थी, जिससे मोदी सरकार की काफी फजीहत हुई थी, इसीलिए बीजेपी आलाकमान को रालोद मुखिया जयंत चौधरी रास आने लगे हैं। जयंत चौधरी यदि बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं तो पश्चिमी यूपी की करीब 20 सीटों का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इसका असर साफ दिखाई देगा। 2014 और उसके हुए चुनाव में भले ही रालोद कुछ खास कमाल ना दिखा पाई हो लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ताकत के साथ उभर कर सामने आयी है। आरएलडी अपनी ताकत का एहसास बीते 2018 कैराना लोकसभा उपचुनाव और 2023 खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी दिखा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से बीजेपी के सामने जाट वोट में बिखराव का खतरा भी कम हो जायेगा।

दरअसल, पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट में एक बड़ा हिस्सा तो जरूर बीजेपी के साथ है, लेकिन अभी तक पार्टी पश्चिमी यूपी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई है। बीजेपी के स्थानीय नेता उतनी चमक नहीं बिखेर पा रहे हैं, जितनी उनसे अपेक्षा थी। यह सच है कि पश्चिमी यूपी के गुर्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, शर्मा, त्यागी जाति के वोट का ज्यादातर हिस्सा भी बीजेपी के साथ है। पूरे यूपी में भले ही जाट समुदाय 4 से 6 फीसदी के बीच हो, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17 फीसदी हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। इन्हीं में 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे हैं। मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं जैसे जिलों में जाटों का काफी प्रभाव है।

बात इससे आगे की कि जाए तो लगता है अबकी से बीजेपी पिछड़ों और दलितों को भी टिकट देने में ज्यादा दरियादिली दिखाएगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रही है, उसकी काट के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। इसके अलावा मुसलमानों को रिझाने के लिए पसमांदा समाज के एक दो प्रत्याशियों को भी टिकट मिल सकता है। बीजेपी पसमांदा समाज के प्रत्याशियों को अपने सहयोगी दलों के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार सकती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए अभी बीजेपी को अपने गठबंधन सहयोगियों से भी बात करनी है। यदि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को अपना दल एस, निषाद पार्टी के साथ-साथ इन दलों के नेताओं की दावेदारी पर भी गौर करना होगा। ऐसे में बीजेपी 65-70 सीटों पर ही चुनाव लड़ती नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, इसके चलते भी बीजेपी के कुछ सांसदों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर से चुनावी तालमेल होता है तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के गाजीपुर के आसपास के जिलों की कुछ सीटें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हिस्से में जा सकती हैं।

उधर, बीजेपी आलाकमान द्वारा मोदी सरकार के नौ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में मौजूदा सांसदों की जनता में पकड़ के साथ छवि का आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही संभावित नए प्रत्याशियों की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में भी पार्टी के सांसदों की जनता में पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता सामने आ रही है। करीब एक दर्जन से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में अभियान के तहत हुई रैलियों में दो-पांच हजार लोग भी नहीं जुटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टी किसी भी स्थिति में वैसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती है, जिन पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है। या फिर जो पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में चढ़ गए हैं। ऐसे सांसदों की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है।

बीजेपी ने अबकी से उन सीटों पर भी इस बार कमल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिन सीटों (मैनपुरी-रायबरेली) पर 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। बीजेपी इन सभी सीटों को जीतने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश की एक-एक सीट का बारीकी से निरीक्षण करके ही प्रत्याशियों को उतारना चाह रही है। पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए भी सर्वे करवाया जा रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

वृषण (अंडकोश) के नीचे सीवन के दोनों ओर दोनों गुल्फों (टखनों) को स्थिर करके पादों को हाथों से बाँधकर (अर्थात थामकर बैठना ही भद्रासन कहलाता है। सीवनी के दोनों पार्श्वों को दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन कहलाता है।

दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थित करके दोनों कोहनियों को नाभि के पार्श्व में दोनों तरफ लगाए, तदनन्तर मयूर की भाँति सम्पूर्ण शरीर को अधर करके सिर और पैरों को ऊपर की ओर उठाये रहना ही मयूर आसन कहलाता है। वाय जाँघ के मूल में दाहिने पैर के अँगूठे को पकड़ने से वह मत्स्येन्द्र आसन कहलाता है। बायें पैर की एड़ी को सीवन पर स्थिर करे और दाहिने पैर को उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखे। इस तरह शरीर को सीधा करके बैठना सिद्धासन कहलाता है। दोनों पैरों को जमीन में फैलाकर दोनों हाथों के द्वारा पैर के अँगूठों को पकड़ ले और पुनः सिर को घुटनों पर स्थित करना पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है। जिस किसी प्रकार से बैठने पर सुख एवं स्थिरता मिले, वैसे ही बैठना सुखासन कहलाता है। जो असमर्थता के कारण अन्य आसनों को न लगा सके, वह इस आसन को लगाये। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया अर्थात् जीत लिया समझना चाहिए।

यम-नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक् रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तदुपरान्त प्राणायाम करना चाहिए। मानव देह (शरीर) का माप (प्रमाण) अपनी अँगुलियों के द्वारा छियानवे अंगुल का है। शरीर से प्राण बारह अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है। शरीर में स्थित वायु को (प्राणायाम द्वारा) शरीर में समुद्भूत अग्नि से योग (प्रक्रिया) द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कान्ति से युक्त त्रिकोण (तीन कोणों से युक्त) अग्नि का स्थान कहा गया है। चार पैरों वाले पशुओं में यह अग्नि स्थल चार कोनों से युक्त (चौकोर) होता है। पक्षियों का गोल- वृत्ताकार, सर्पजाति वालों का छः कोने का एवं स्वेदजों का आठ कोण (कोने) का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर नौ अंगुल प्रमाण से युक्त कन्द का निवास कहा गया है, जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है। वह चार अंगुल ऊँचा और चार अंगुल चौड़ा होता है।

क्रमशः ...

ताकि किसी और को न होना पड़े शर्मिंदा...

उत्तम सिन्हा

ट्रेनों व सार्वजनिक शौचालयों में लिखे अश्लील कमेंट्स को 7 मिटाने की मुहिम जारी है। भद्दी टिप्पणियाँ साफ कर, लिख रहे - कृपया अश्लीलता न फैलाएँ, इस शौचालय का प्रयोग आपकी माँ-बहन भी करेंगी। यह मुहिम झारखण्ड के धनबाद में चलाई जा रही है। स्टेशन से गुजरने वाली हर एक ट्रेन, शहर के हर एक पार्क, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी इमारतें, बस स्टेंड... इसकी जद में है। महज एक साल पहले की बात है। धनबाद के गाँधी नगर के उत्तम सिन्हा कोलफील्ड एक्सप्रेस से हावड़ा से धनबाद आ रहे थे। साथ में पत्नी अपर्णा और आठ साल की बेटी वर्षा भी थी। ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि बेटी बोली-पापा! टॉयलेट जाना है। उत्तम उसे शौचालय तक ले गए। बाहर आने के बाद बेटी ने शौचालय के अंदर दीवारों पर लिखी इबारत के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे कि वे स्तब्ध रह गए। बेटी के सवालों ने उनको झकझोर दिया। अंदर गए और शौचालय की दीवार में लिखे अश्लील वाक्य तत्काल मिटाए। तब से लेकर अब तक उत्तम विभिन्न रूट्स की ट्रेनों में 250 से अधिक शौचालय की दीवारों पर लिखे अपशब्द मिटा चुके हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात इन दीवारों पर न लिखें। जिनहें आपकी माँ, बहन व घर के सदस्य पढ़कर शर्मिंदा हों। कोई ऐसा करता है तो उन्हें रोके। अश्लील कमेंट मिटाने के बाद उत्तम ट्रेन की दीवार पर पोस्टरनुमा कागज चिपकाते हैं, जिस पर लिखा होता है-स्टॉप राइटिंग, इस शौचालय का प्रयोग आपकी मा-बहन भी करेंगी।

उत्तम का कपड़े का कारोबार है। वे अकसर पटना, छपरा, कोलकाता, छत्तीसगढ़, लखनऊ, कानपुर और लुधियाना जैसे शहरों में जाते हैं। इस रूट की लगभग सभी ट्रेनों में वे सफर करते हैं। इस दौरान ट्रेन के शौचालयों में अश्लील टिप्पणियाँ लिखी दिखती हैं तो उसे तत्काल मिटाते हैं। ट्रेन के शौचालय से शुरू की मुहिम को उत्तम ने विस्तार दिया है। अब वे पार्क, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड और होटल के शौचालयों में लिखे अश्लील टिप्पणियों को भी मिटा रहे हैं। एक वर्ष में उत्तम पार्क, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, होटल आदि के 180 शौचालयों में लिखे गंदे कमेंट्स मिटा चुके हैं। उत्तम की पत्नी अपर्णा भी इसकी सराहना करती हैं। दो टूक कहती हैं कि पति ने ऐसी मुहिम शुरू की जिससे सभी को सबक लेना चाहिए। वहीं उत्तम कहते हैं कि ऐसा काम करने वालों को लिखने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कभी उनके घर के सदस्य इस शौचालय का प्रयोग करें। उन पर क्या बीतेगी। सोच कर देखिए। आत्मा तक शर्मसार होगी। फिर ऐसा काम क्यों? हम जो कर रहे हैं उससे अंतस को शांति मिलती है।

तालिबान क्यों कर रहा है चीन का स्वागत?

बिक्रम उपाध्याय

खनिज और पेट्रोलियम दोहन के समझौते के साथ अफगानिस्तान में घुसने वाला चीन अब तालिबान लैंड में पैर जमाने के लिए रेल और रोड नेटवर्क अफगानिस्तान तक ले जा रहा है, बस उसे खौफ है इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से जो चीनियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। चीन पहले ही किर्गिस्तान की सीमा पर झिंजियांग के काशगर तक एक रेलवे लाइन बिछा चुका है। वह सड़क मार्ग से किर्गिस्तान व उज्बेकिस्तान तक भी पहुंच चुका है। चीन की शिपमेंट कंपनियां इसी तरह अफ़गानिस्तान एक्सप्रेस मार्ग के भी तैयार होने की उम्मीद कर रही हैं। अफगानिस्तान में ईटीआईएम चीन के प्रति बेहद आक्रामक है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान अपनी प्रतिबद्धता को ईमानदारी से निभाए और दृढ़ संकल्प के साथ ईटीआईएम सहित सभी आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसे। जब तक अफगानिस्तान में चीन और अन्य देशों के नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक चीनी निवेशक खुलकर अफगानिस्तान की ओर रुख नहीं करेंगे।

मौजूदा तालिबान सरकार चीन के साथ वह हर समझौता करने के लिए तैयार है जिससे उसे पैसा मिल सके। पूरी दुनिया से कटे अफगानिस्तान के लिए चीन एकमात्र आशा का केंद्र है, क्योंकि तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देने के बावजूद चीन हर किस्म के समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। अफगानिस्तान के मसले के राजनीतिक समाधान के लिए सभी वैश्विक मंचों पर तालिबान की वकालत भी कर रहा है।

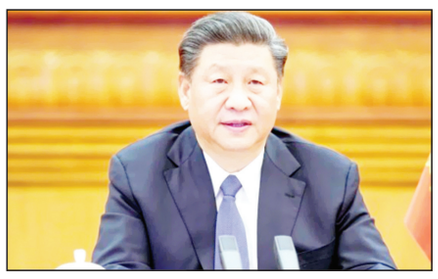

हाल ही में भारत के नेतृत्व में हुई एससीओ बैठक में चीन ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भेजने और वहां स्थाई शांति की कोशिश का समर्थन किया था। एससीओ मे अपना समर्थन देख तालिबान प्रशासन ने यह मांग भी रख दी है कि एससीओ अपनी भविष्य की बैठकों में अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करे। कतर स्थित तालिबान के प्रतिनिधि सुहैल शाहीन ने एक समाचार चैनल के जरिए यह मांग रखी।

एससीओ पर विदेश मंत्रियों की बैठकों में भी चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अपने पक्ष रखे और गोवा से निकलते ही चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में मिले। वहां अफ़गानिस्तान को इस बात के लिए राजी किया गया कि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी-पैक में शामिल होगा।

चीन के लिए सी-पैक एक डेड प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, जिसमें उसे अपना 6 अरब डॉलर का निवेश डूबता दिखाई दे रहा है। भारत के विरोध और बलूचों के हिंसक बॉयकाट के कारण पाकिस्तान और चीन दोनों के हौसले पस्त हो गए हैं। फिर पाकिस्तान इस कदर कर्ज में डूब चुका है कि अब वह सी पैक में पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है। चीन इसलिए ईरान और अफ़गानिस्तान को सी-पैक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है।

दरअसल चीन अफगानिस्तान के खनिज-समृद्ध भूभाग पर अकेले खेलने का मंसूबा बना रहा है। हाल ही में अफ़गानिस्तान के लिथियम भंडारों का दोहन करने के लिए चीन ने अरबों का सौदा किया है। लिथियम ऊर्जा के स्रोत बैटरी का प्रमुख इनपुट है। लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक में इसका उपयोग होता है। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश के उत्तर में तेल की खोज एवं उत्पादन के लिए भी एक चीनी कंपनी के साथ ही अनुबंध किया है। 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद किसी विदेशी फर्म के साथ पहला बड़ा ऊर्जा समझौता है।

पर चीन के लिए अफ़ग़ानिस्तान में पांव पसारना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए उसे अपने नागरिकों और अधिकारियों की जान की कुर्बानी भी देनी पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीनी हितों के खिलाफ हमलों में तेजी आई है। 2018 के बाद से, पाकिस्तान के अंदर चीन के खिलाफ कम से कम पांच हमले किए गए। अगस्त 2018 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने डालबैंडियन में आत्मघाती हमला कर तीन चीनी नागरिक घायल कर दिए। नवंबर 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर बीएलए द्वारा किए गए हमले में चार पाकिस्तानियों की मौत हो गई। जून 2021 में उत्तर-पश्चिमी खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान में एक बस पर हमला कर नौ चीनी श्रमिकों को मौत की नींद सुला दी। उसके बाद चीनी इतने डर गए कि बांध पर काम बंद कर वहां से भाग लिए।

अफ़ग़ानिस्तान में चीनियों पर हमले आईएसआईएस से जुड़ा संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस (आईएस-केपी) भी कर रहा है। तालिबान से खोई जमीन वापस पाने के लिए आईएस-केपी की रणनीति मध्य एशिया से किसी भी विदेशी ताकत को बाहर रखने की है। इस आतंकवादी संगठन ने 12 दिसंबर, 2022 को काबुल के लोंगन होटल को निशाना बनाया, जहां चीनी निवेशक ठहरे हुए थे। हमले में कम से कम तीन लोग मारे गए और 18 से अधिक घायल हो गए, जिनमें पांच चीनी नागरिक भी थे।

प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतना जोखिम लेकर चीन अफ़ग़ानिस्तान में क्यों अपनी पैठ बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ इसके तीन कारण बता रहे हैं। पहला यह कि चीन ने ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों में जो निवेश कर रखा है, उसकी सुरक्षा के लिए तालिबान का साथ जरुरी है, क्योंकि अधिकतर आतंकवादी संगठन अफ़ग़ानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं और उन पर लगाम तालिबान ही लगा सकते हैं। इसे बीजिंग की हेजिंग पॉलिसी भी कहा जा रहा है।

दूसरा, चीन सी-पैक को लेकर चिंतित है। अफ़ग़ानिस्तान के शामिल होने से परियोजना में गति आ सकती है और तीसरा सबसे बड़ा कारण अफ़ग़ानिस्तान में मिनरल्स और पेट्रोलियम का भंडार, जो इस समय चीन को ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस बनाये रखने में काम आ सकता है। इसीलिए जब कोई अफ़ग़ानिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है तो तालिबान के लिए भी चीन किसी मेहरबान के समान है।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन प्रार्थना (भाग-2)

गतांक से आगे...

दिन भर का कार्यक्रम निबटाकर शयन से पूर्व प्रार्थना करना अनुचित है। उन्होंने घोषणा की कि हम चाहे कहीं भी रहें, सायंकालीन प्रार्थना सात बजे होगी और इस घटना के बाद बापू और उनके संग-साथ के सभी लोग, जंगल में होते या बस्ती में, शाम की प्रार्थना ठीक सात बजे कर लिया करते। गोलमेज परिषद् के समय लंदन में एक दिन सी. एफ. एंड्रयूज ने जब बापू से शाम को कुछ अंग्रेज पादरियों द्वारा स्वागत किए जाने तथा सात बजे लंदन के लाट पादरी के आवश्यक कार्यवश आने के संबंध में कहा, तब उन्होंने तीव्र दृष्टि से ऊपर देखा और कहा-सात बजे की प्रार्थना का क्या होगा? एंड्रयूज बोले-आगे-पीछे कर लेंगे। बापू ने रास्ते में मोटर में ही प्रार्थना कर लेने का निश्चय किया। सरदार पटेल से बातें करने में तन्मय हो जाने के फलस्वरूप दिल्ली में सायंकाल की अंतिम प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने में बापू को कुछ विलंब हो गया। उस समय भी उनकी आत्मग्लानि स्पष्ट झलक रही थी। काका साहब कालेलकर के शब्दों में-अनिश्चितता, अव्यवस्था और ढीलापन वे बिलकुल सहन नहीं कर सकते थे। कर्तव्यपालन में उनकी ओर से कभी प्रमाद नहीं होता और कदाचित् तनिक प्रमाद हो जाता तो वे दुखी होते और अपने प्रति उनकी इतनी नाराजगी होती कि वही बड़ा प्रायश्चित होता। सब व्यक्तियों के प्रति क्षमासागर होते हुए उन्होंने अपने प्रति तनिक क्षमा-वृत्ति नहीं धारण की। वे हमेशा कहते कि मनुष्य का सारा जीवन हर क्षण विचारमय होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में यह साधना पूरी की और इस तरह अपना सारा जीवन प्रार्थनामय बनाया। स्थितप्रज्ञ एवं अनासक्त होने की बापू की इच्छा और कोशिश बराबर रहती । सतत प्रयास करने से व्यक्ति अवश्य सफल होता है। समस्त आर्थग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि प्रभु का अंतस्मरण जीवात्मा के विश्वात्मा में विलीन होने की स्पष्ट सूचना है। जनम-जनम मुनि जतन कराहीं अंत राम कहि आवत नाहीं॥ अंतिम समय उनके श्रीमुख से राम शब्द ही निकला था।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चंद्रवंशी ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री महेश चंद्रवंशी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को श्री चन्द्रवंशी ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में अपने विगत 2 वर्ष के कार्यकाल का वेतन समाज के जरुरतमंद लोगों के सेवार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करते हुए दो लाख चालीस हजार रुपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री चन्द्रवंशी ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों की मदद हेतु किये जा रहे प्रयासों में आर्थिक सहयोग देते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सदस्य श्री चंद्रवंशी के इस संवेदनशील कदम की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया।

मरम्मत कार्य के लिए आज बंद रहेगा सिलयारी रेलवे फाटक

रायपुर। रायपुर रेल मंडल के सिलयारी फाटक स्टेशनों के मध्य स्थित समपार फाटक क्रमांक 405 (सिलयारी) के अप लाइन किमी. 805/23- 25) सिलयारी गेट पर रेलवे के आवश्यक मरम्मत का कार्य हेतु बंद रखा जाएगा। रेलवे सूत्रों ने बताया कि दिनांक 13.07.2023 को रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 15.07.2023 को शाम 06:00 बजे रात्रि तक रहने की संभावना है। अत: अतिआवश्यक मरम्मत कार्य हेतु समपार सड़क आवागमन बंद करना आवश्यक है। रेल यातायात व यात्रियों की संरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं । रेल प्रशासन सभी से सहयोग की आशा करता है।

मुख्यमंत्री से जूनियर डॉक्टर्स एसो. के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसोसिएशन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. प्रेम चौधरी, डॉ. गौरव परिहार, डॉ. प्रीतम प्रजापति, डॉ. हिमांशु सिन्हा तथा डॉ. गगन मोहन आदि उपस्थित थे।

अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 30 को

रायपुर। डॉक्टर, सीए, सीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जब वे 30 जुलाई को अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा एवं महिला मंडल इकाई द्वारा युवक - युवती परिचय सम्मेलन में अपने लिए जीवन साथी तलाश कर सकती है। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 30 कोअग्रवाल महिला मंडल इकाई की प्रचार - प्रसार प्रमुख ज्योति अग्रवाल ने बताया कि युवक - युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 30 जुलाई को प्रात: 10 बजे से जवाहर नगर के अग्रसेन भवन में किया गया है। इस सम्मेलन में डॉक्टर, सीए, सीएस की पढ़ाई करने वाली युवक-युवती अपने लिए जीवन साथी की तलाश करने के लिए 20 जुलाई तक पंजीयन करवा सकती है। इसके लिए अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष डॉ नीरज अग्रवाल - 9827164587, किशोर अग्रवाल - 9039378341, महिला मंडल की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल - 9424230427 से संपर्क किया जा सकता है।

दैवेभो कर्मचारी संघ ने टीएस सिंहदेव को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। नियमितीकरण की बाट जोह रहे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वन विभाग के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक रामकुमार सिन्हा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलनारायण साहु, प्रदेश सलाहकार तुलसीकृत डोंगरे, वन विकास निगम के अध्यक्ष जनक लाल साहु, परिक्षीत यादव व छ. ग. उधानिकी विभाग के महामंत्री विजय पटेल ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रदेश भर के 30731 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भर में कार्यश्रत् 30, 731 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वाहन चालक/ कम्प्युटर आपरेटर/ कार्यालय सहायक/दैनिक श्रमिक/तेन्दुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिकों को नियमितीकरण एवं स्थायीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नियमितीकरण एवं स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकरण करने पर कितना वित्तीय भार आयेगा उसका प्रस्ताव सौंपा गया है।

राहुल के समर्थन में कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर जता रही विरोध

भूपेश बघेल समेत दिग्गज नेता शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मौन सत्याग्रह में खुद सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के विरोध में यह सत्याग्रह किया जा रहा है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के लिए समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए यह मौन सत्याग्रह रखा है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित दिग्गज छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम न डरेंगे न झुकेंगे।

रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के तमाम नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अयोग्यता के पीछे बीजेपी की घटिया चाल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए नई तरकीबें ढूंढ रही है, क्योंकि

मोदी सरकार सच सुनने से घबराती है।

फैसले के विरोध में सत्याग्रह का किया था ऐलान- 9 जुलाई को कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने वाले फैसले के विरोध में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह आयोजित करने का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई थी।

कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन

जगदलपुर। बुधवार को राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर आहुत मौन सत्याग्रह के दौरान मुंह पर काली पट्टी लगाकर उन्होने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विरुद्ध किए जा रहे केंद्र सरकार की साजिशों के खिलाफविरोध जताया। इस दौरान श्री जैन के साथ एमआइसी सदस्य यशवर्धन राव, पार्षद सूर्या पानी, वरिष्ठ नेता गौरनाथ नाग, हेमू उपाध्याय, संतोष सिंह व अन्य मौजूद थे।

कांग्रेस का मौन सत्याग्रह पिछड़ा वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला : अरुण साव

रायपुर। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थन में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के इस मौन प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं पर एक परिवार की चाटुकारिता करने और न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अरुण साव ने राहुल गांधी पर पिछड़ा वर्ग के अपमान करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से उन्हें दोषी ठहराए जाने का भी जिक्र किया। ऐसे में कांग्रेस के सत्याग्रह पर सवाल उठाते हुए अरुण साव ने उसे पिछड़ा वर्ग को गाली देने वालों के साथ खड़े होने का इल्जाम लगाया। अरुण साव के मुताबिक कांग्रेस का जो रवैया है, उससे यह स्पष्ट है कि आज अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती तो वह राहुल गांधी की चाटुकारिता के लिए आपातकाल लगाने से भी नहीं चूकती। कांग्रेस देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखती। वह केवल एक परिवार को ही सब कुछ मानती है। देश की जनता भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के प्रदर्शन को न्यायपालिका के खिलाफ बताते हुए इसे संविधान का मजाक उड़ाने वाला बताया। साथ ही कांग्रेस पर गांधी परिवार के आगे देश के संविधान को भी नहीं मानने और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खंडित करने वाला बताया।राहुल गांधी की संसद सदस्यता के मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है तो वहीं अरुण साव ने पलटवार कर कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए वार पलटवार को सिलसिला छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा हैं। दोनों ही पार्टियां हर मुद्दे को लपकने की कोशिश में है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कामयाबी किसके हिस्से आती है।

ईडी की कार्रवाई राजनीति से है प्रेरित रमन की नीति से हो रही शराब बिक्री

रायपुर। कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से प्रदेश में राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी पहले छत्तीसगढ़ में ईडी भेजकर गलत कार्रवाई करती है।इसके बाद पटकथा के आधार पर बयान जारी कर रही है। इसके बाद ईडी के बयान पर बीजेपी राजनीति करती है।कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी को लेकर भी भाजपा झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर किसानों के कर्ज माफी की बात की थी ना कि शराबबंदी की।

कांग्रेस की माने तो ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ईडी कार्रवाई के बाद पहले से ही तैयार किए गए स्क्रिप्ट के आधार पर कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर साढ़े चार साल में एक भी रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं।इसका कोई प्रमाण नहीं है।इसलिए अब बीजेपी झूठे आरोपों को आधार बनाकर ईडी को आगे रखकर कांग्रेस को बदनाम कर रही है।छत्तीसगढ़ में बिना एक्साइज ड्यूटी पटाये शराब बिक्री करने से 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। यदि ईडी के आरोप सही है तो ईडी ने शराब निर्माण के विक्रय के डिस्टलरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं किया?

डिस्टलरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ईडी- ईडी की कार्यवाही कहीं सुनी बातों के आधार पर बिना तथ्य के हैं। राज्य में 2012 में रमन सरकार ने देशी शराब के उत्पादन का अधिकार मात्र राज्य के ही मात्र 3 डिस्टलरों दिया था। अन्य किसी डिस्टलर को उत्पादन निविदा में भाग लेने का अधिकार समाप्त हो गया था।रमन सरकार ने ही 2017 मे शराब विक्रय का एकाधिकार सरकारी कम्पनी को सौंपा। रमन सरकार के कार्यकाल के अंतिम वित्तीय वर्ष मे शराब से कुल राजस्व 3900 करोड़ था।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शराब नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। व्यवस्था भी पूर्ववत रही। उसके बावजूद वर्ष 2023 रमन राज की अपेक्षा शराब का राजस्व 3900 से बढ़कर 6500 करोड़ हो गया। बिना एक्साइज ड्यूटी शराब बेचने की शिकायत की जांच राज्य सरकार 3 डिस्टलरों पर करवा रही है।

कांग्रेस की माने तो रमन सरकार के दौरान दो कैबिनेट मंत्री शराब के अवैध कमाई को लेकर भिड़े थे। रमन सिंह के राज में शराब नीति में परिवर्तन करके और शराब के ब्रांडों के रेट के निर्धारण में गड़बड़ी करके 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। जैसे शराब नीति में दिल्ली में परिवर्तन किया गया वैसा ही परिवर्तन रमन राज में छत्तीसगढ़ में हुआ।

टिकट की चाह में ठगा गए भाजपाई, दे दिए लाखों रूपए

रायपुर। विधानसभा चुनाव लडने के इच्छुक भाजपा नेताओं के साथ ठगी का मामला सामने आने से पार्टी में खलबली मच गई है कि ऐसा भी होने लगा है लेकिन इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं हैं। अनजान लोगों के चक्कर में वे लोग फंसे जो ऐन-केन सर्वे सूची में नाम जुड़वाकर अपनी ब्रांडिंग दिल्ली में करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने लाखों रूपए दे दिए अब उन्हे पता चला कि वे ठगा गए तो होश उड़ गए,पार्टी के अंदर बाहर किरकिरी हो रही है सो अलग। पार्टी नेताओं ने मामले से पल्ला झाड लिया है।

मामला यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सर्वे में नाम जुड़वाने के नाम पर नेताओं से लाखों रुपये वसूल लिए गए। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो दिल्ली के कुछ युवाओं ने फेसबुक पर अमित शाह और उनके पीए के साथ तस्वीर दिखाई। उसके बाद उन युवाओं ने अपना खेल शुरू किया। सर्वे सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी से पांच लाख तो किसी से आठ लाख रुपये वसूल लिए।

ठगी के शिकार वह नेता हुए हैं, जिनकी सक्रियता इंटरनेट मीडिया पर ही नजर आती है। क्षेत्र में पार्टी के कार्यक्रम और अन्य अभियान में उनकी उपस्थिति शून्य रहती है। इसमें राजधानी रायपुर के दो युवा नेता हैं। एक जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि एक युवा मोर्चा की जिला कार्यकार्यकारिणी में है। एक नेता कांकेर जिले के हैं, जो पेशे से इंजीनियर हैं और पार्टी के बड़े नेताओं के इर्द-गिर्द अक्सर पाए जाते हैं। ऐसे ही गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी के एक-एक नेता का नाम सामने आ रहा है, जिनसे पैसे वसूले गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से इस तरह की ठगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया।

राजीव युवा मितान योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में निभा रहे हैं सक्रिय भूमिका

रायपुर। देश को समृद्ध बनाने में युवाओं की भूमिका अहम मानी जाती है। युवाओं की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो वह राज्य तेजी से आगे बढने लगता है।

युवाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया, ताकि युवा क्लब से जुड़कर राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री श्री बघेल के द्वारा 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के अवसर पर की गई थी। इस योजना का विधिवत शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। प्रदेश में 13 हजार 261 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाने का लक्ष्य है। आज तक 13 हजार 242 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन हो चुका है। योजनानुसार प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा हैं। जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हैं। प्रत्येक क्लब को प्रति तीन माह में 25 हजार रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह हर वर्ष क्लब को एक लाख रूपए मिलेंगे। राजीव युवा मितान क्लबों को अब तक 63 करोड़ 77 लाख रूपए से अधिक की राशि आबंटित की जा चुकी है। राजीव युवा मितान क्लब का गठन का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोडने के अलावा युवाओं के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है। क्लब से जुड़कर युवा खेलों को आगे बढ़ाने के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यावरण के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने योजना शुरू करते हुए कहा था कि युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढने में करेंगे।

अवैध कारोबार के विरूद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही के पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश

रायपुर। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा द्वारा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली गई। बैठक में विगत माह में जिलों के द्वारा उपरोक्त अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई एवं पुलिस अधीक्षकों को ऑनलाईन गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरूद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने एवं इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी वैधानिक तथा प्रतिबंधक कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये।

बैठक में चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा कुर्की, नीलामी का आदेश किया जा चुका है, उन प्रकरणों की सम्पत्तियों की शीघ्र नीलामी की जाकर प्राप्त राशि निवेशकों को वापस की जावे। इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करें।

आगामी प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सक्रिय अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध कर कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एन.एस.ए एवं जिला बदर के तहत् प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने एवं फरार अपराधियों एवं वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनों में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में की जा रही कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी। अतः पुलिस अधीक्षकगण विशेष रूचि लेकर इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पूर्व विधायक ओंकार शाह ने छोड़ी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक माहौल बदल रहा है। बिंद्रानवागढ़ के पूर्व विधायक ओमकार शाह ने अपनी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कहा कि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के संपर्क में हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है कि वे जल्द किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं।

शाह को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज

ओंकार शाह ने कहा है कि चुनावी साल में ओंकार शाह का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ छोड़ना अनेक संकेतों की ओर इशारा करता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर कुमार ओंकार शाह ने गोंगपा ज्वाइन किया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। 2018 में उनको लगभग 19 हजार से अधिक वोट मिले थे। जानकारों का मनाना है कि इस सीट पर शायद यही कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा।

2 बार कांग्रेस विधायक रहे हैं

ओंकार शाह बिंद्रानवागढ़ से 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर सन् 1993 और 2003 में ओंकार शाह चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से लेकर अब तक यह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ही विधायक जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस से दो बार विधायक का चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व करने वाले ओंकार शाह राज परिवार से आते हैं। पिछले कुछ समय से शाह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किनारा कर लिया था। लेकिन आज उन्होने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

जोशी अहिवारा में कर रहे हैं मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनसंपर्क

न्यायाधीश की एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना था अनिवार्य, अब जनसेवा करने तैयार

अहिवारा। जनसेवा का भाव शुरू से था पर न्यायाधीश की एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना होता है इसलिए वे अहिवारा विधानसभा की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब वे सेवानिवृत हो चुके है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों और राज्य सरकार की खामियों को लेकर जनता के बीच जाकर सघल जनसपंर्क अभियान कर रहे है। उक्त विचार सेवानिवृत जज अग्रलाल जोशी ने कहीं।

उन्होंने कहा कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव तक भारतीय जनता पाटी की विचारधारा को पहुंचाने में वे अभी से जुट गए है क्योंकि आगामी दिनों विधानसभा चुनाव होने वाला है और वे पार्टी की ओर से टिकट की दावेदारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौ साल की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक पहुंचा रहे हैं। विचारधारा संघ की थी, विचारधारा राष्ट्रवाद का था

इसलिए न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत होने के बाद तन मन से राष्ट्र सेवा में लग गए। आज उनके नाम की चर्चा पूरे अहिवारा में हो रही है। दरअसल अग्रलाल जोशी अहिवारा के गांव-गांव, शहर-शहर में भाजपा की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ताउम्र न्याय की सेवा की, अब जनसेवा के लिए मैदान में उत रहे है। इस उम्र में जब सेवानिवृति के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, उत्साह खो बैठते हैं, तो वहीं अग्रलाल जोशी का उत्साह देखते बनता हैं।

सुबह से ही वह अहिवारा विधानसभा में सक्रिय हो जाते हैं और हर दिन किसी ने किसी गांव में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत व नगर पालिका, नगर निगम के वार्डों में जाकर आम जनता की समस्याओं से रुबरु होने के साथ ही सुख और दुख में शामिल हो रहे है।

अग्रलाल जोशी ने कहा कि जनसेवा का भाव शुरू से था पर न्यायाधीश की एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। हम एक नियम व कायदे से बंधे होते हैं और खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। फिलहाल अब सेवानिवृत हो चुका हूं और शुरु से ही भाजपा से एक लगाव भी रहा है, तो भाजपा के माध्यम से जनसेवा की भावना को लेकर वे जनता के बीच जा रहे है। उन्होंने बताया पार्टी मेरी माँ है ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हुँ जैसा एक बच्चा अपनी माँ की गोद मे महसूस करता है, फिलहाल तो एक ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना है, उनकी समस्याओं को दूर करना।

ग्राम मुर्रा में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने आम नागरिकों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में आए थे अपने भाषण से यहां के लोगों में ऊर्जा डालकर गए है। उनके 9 साल के कार्यकाल को देखें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी वे जीतकर आएंगे और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर एक बार कुर्सी में बैठेगा और कांग्रेस पार्टी का सफाया करना है। पीएम मोदी ने 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया है। हर गरीब के सिर में छत देने के लिए पीएम आवास के तहत 2.5 लाख रुपये की सहायता, महिलाओं के लिए उज्जवला योजना के तहत गैस चूल्हा, आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपये, 6 हजार रुपये किसानों के खाते में आता है ऐसे ही कई योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। पीएम मोदी की नौ साल के कार्यकाल में भारत ने कितनी तरक्की की है और कैसे जन जन का कल्याण हुआ है यहां के लोगों को प्राथमिकता से बताना है।

मोदी सरकार ने दिया दो खेल अकादमी का उपहार

प्रदेश अध्यक्ष साव व सांसद संतोष पांडे ने जताया मोदी सरकार का आभार

■ खेल प्रतिभाएं विश्व स्तर पर अपना कौशल दिखाएंगी- साव

रायपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया की दो एकेडमी का उपहार देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि बहूत ही गर्व का विषय है कि बास्केटबॉल की नर्सरी राजनांदगांव में खेलो इंडिया की दो एकेडमी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव एवं युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव को बास्केटबाल खेल की बालक एवं बालिकाओं की ऐक्रिडिएटेड एकेडमी बनाने की स्वीकृति भारत शासन ने प्रदान की है। इस एकेड़मी के लिए चयनित खिलाड़ियों पर भारत सरकार 6 लाख 28 हजार रुपये सालाना खर्च करेगी। मोदी सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं के वैश्विक स्तर पर उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय को उनके प्रयास की सफलता पर बधाई देते हुए राज्य की खेल प्रतिभाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री साव ने आव्हान किया कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं मोदी जी की मंशा के मुताबिक खेलो इंडिया के विराट अभियान का हिस्सा बनकर देश दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खेलों की दुनिया में वैश्विक मानचित्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्होंने हर टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विजेता बने, उनका सम्मान किया और जो सफलता से चूक गए, उन्हें सफलता के मंत्र दिए। जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों ने आगे चलकर देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। इसी का परिणाम है कि आज भारत के खिलाड़ी विश्व में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के बड़े-बड़े टूर्नामेंटों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों के विकास और खिलाड़ियों की सुविधा, उनकी प्रतिभा के विकास के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ को दो खेल अकादमी स्वीकृत की गई हैं। जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में सामने आएंगे और हमारे प्रदेश की खेल प्रतिभाएं विश्व स्तर पर अपना कौशल दिखाएंगी। सांसद संतोष पांडेय ने भी राजनांदगांव वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि जनविकास की नीति व निरंतर प्रयासों से यह सफलता मिल पाई है।

पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली देने वाले के समर्थन में मौन सत्याग्रह कर रही कांग्रेस

रायपुर। पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने वाले राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग को गाली दी ,उसका उपहास उड़ाया अपमान किया, न्यायालय ने जिसे ना सिर्फ दोषी ठहराया बल्कि सजा भी दी एवं दोबारा याचिका लगाने पर भी उसे रद्द किया ऐसे व्यक्ति के लिए मौन धारण कर प्रदर्शन करना व उसे सत्याग्रह का नाम देना पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कृत्य है कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पिछड़े वर्ग के साथ नहीं पिछड़े वर्ग को गाली देने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है।श्री साव ने कहा कांग्रेस का जो रवैया है उससे यह पूर्णत- स्पष्ट है कि आज अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती तो वह राहुल गांधी की चाटुकारिता के लिए शायद आपातकाल लगाने से भी नहीं चूकती जैसा कि इंदिरा गांधी के लिए लगाया गया था।कांग्रेस देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नही रखती वह केवल एक परिवार को ही सब कुछ मानती है देश की जनता भी इनकी प्राथमिकता में नही है।श्री साव ने कहा न्यायपालिका जिस पर सभी का भरोसा होता है आज कांग्रेस उसके खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है यह देश के संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है जनता अब यह मान रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार के आगे देश के संविधान को भी नहीं मानती और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खंडित करने का कुंठित प्रयास करती है पूरे देश की जनता कांग्रेस का यह कृत्य देख रही है।

■ अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए फिर से आपातकाल लगा देती

रमन सिंह का सीएम भूपेश बघेल पर तंज

भूपेश को आता है ईडी की सपना इतना डर किस बात का : डॉ. रमन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर-आजमाइश में लगे हैं। इन सबके बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, प्रत्याशी कौन होगा यह पार्टी तय करती है। पार्टी के आदेश का पालन किया जाएगा। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है। यही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को राजनांदगांव के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे।

भूपेश को सपने में दिखती है ईडी

भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए रमन सिंह ने कहा कि, प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर पूर्व सीएम ने निशाना साधा। कहा कि, भूपेश बघेल रात दिन सपना शायद ईडी का ही देखते हैं। उठते हैं तो मेरा नाम लेते हैं, सोते हैं तो ईडी का सपना देखते हैं। इतना भय किस बात का है। मैं तो कहता हूं जब हम ठीक काम कर रहे हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

शराब लूट में दो हजार करोड़ खाने का काम किया

रमन सिंह ने कहा कि, ईडी ने 13000 पेज का दस्तावेज प्रमाण सहित न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसमें इनके कार्यकाल में किए गए घोटालों का खुलासा होगा। अभी 16 से ज्यादा लोग जेल में हैं। आईएएस अफसर जेल में हैं। अगर भूपेश बघेल और सरकार बेदाग है तो इन लोगों की जमानत क्यों नहीं हो रही है। आईएएस अधिकारी जेल में क्यों हैं। कोर्ट इनके बेल को रिजेक्ट बार-बार क्यों कर रही है। यह प्रमाणित हो चुका है संगठित गिरोह शराब के लूट में दो हजार करोड रुपए खाने का काम इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि, हिंदुस्तान की पहली सरकार है, जहां सरकारी दुकान पर 30 प्रतिशत शराब विदाउट हॉल मार्क बेची जा रही है। यानी नकली शराब बेच रहे हैं। शराब दुकान में दो काउंटर हैं, जो कहीं नहीं होगा। एक सरकारी काउंटर और एक प्राइवेट काउंटर हैं। ऐसा भ्रष्टाचार का नमूना भूपेश ही प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए रात को उसको ईडी दिखती है। पूर्व सीएम ने इस दौरान कोरकोट्टी हमले में शहीद एसपी सहित 29 जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ: चंदेल

■ इंटरव्यू लिस्ट में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का नाम नहीं; ष्टरू की युवाओं से मुलाकात पर कसा तंज

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, अब राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि, सहायक शिक्षक भर्ती इंटरव्यू में बुलाए गए 35 अभ्यर्थियों की लिस्ट में चयनित हुए 26 अभ्यर्थियों की लिस्ट साफ बता रह है। उन्होंने लिखा-चयनित सूची में प्रथम स्थान पर निर्भय कुजूर और तीसरे स्थान पर पूर्णिमा सिंह हैं, इनके नाम इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है ही नहीं, तो इनका चयन कैसे हुआ। चंदेल ने कहा पहले सीजी पीएससी घोटाला, फिर व्यापम घोटाला अब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है।

उधर, उनके इस ट्वीट को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जिसमें भाजपा प्रवक्ता नलिनेश ठोकने ने इस विषय पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री की युवाओं से होने वाली भेंट मुलाकात को लेकर भी तंज कसा। ठोकने ने कहा- यह भेंट मुलाकात नहीं, सेट मुलाकात है।ठोकने ने कहा -इस आयोजन में कौन सा व्यक्ति क्या बोलेगा। कौन उनसे मिलेगा। सीएम के सवालों का क्या जवाब देना है। यह सब पहले से ही प्लान किया जाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि इस कार्यक्रम में जाकर अपने साथ साढ़े 4 सालों में हुए धोखे को लेकर सवाल पूछें।

बेरोजगारी भत्ता अंतिम महीनों में ही क्यों

नलिनेश ठोकने ने कहा कि सीएम बघेल प्रदेश के लाखों युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, भेंट मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इसे केवल कुछ युवाओं को ही क्यों दिया जा रहा है।भाजपा नेता नलिनेश ने कहा कि बेरोजगार युवा मेहनत करके व्यापमं की परीक्षा देता है। मगर वहां पर व्यापमं भी उसे ठग लेता है, उसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर का चार विकल्पों में एक ही विकल्प होता है। नलिनेश ने आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है, जो इस सरकार ने निकाला है। इसमें प्रश्न पत्र लीक न कर अपने लोगों को सीधा उत्तर ही बता दिया जाता है।

कांग्रेस बोली-इनके पास मुद्दा ही नहीं

वहीं नारायण चंदेल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है कि भाजपा प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में इनके पास ना योजना है, ना नेता हैं, ना नीति है।

सीएम के सलाहकार शर्मा ने गौठानों का किया निरीक्षण

रायपुर । मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने आज शहर के धरसींवा विकासखंड के गौठान दतरेंगा, धनेली, भटगांव स्थित गौठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने गौठानों में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्री शर्मा ने रायपुर शहर के आसपास विचरण करने वाले आवारा पशुओं को रखने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन तीनों गौठानों में आवारा पशुओं के रहने, खाने और पीने का पानी का उत्तम प्रबंध करें। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा तथा विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

कांग्रेसी बताएं कि अभी उनका महामंत्री कौन है?: कश्यप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि भाजपा की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर अनावश्यक दखल देने और प्रदेश में भ्रम पैदा करने की नाकाम कोशिशों की प्रवृत्ति से कांग्रेस और प्रदेश सरकार के लोग बाज आ जाएँ। श्री कश्यप ने कहा कि भाजपा की फिक्र में प्रलाप करने के बजाय कांग्रेस के लोग अपने सत्ता-संगठन में चल रहे घमासान से उबरने के रास्ते ढूंढ़ने में अपनी उर्जा लगाएं तो शायद यह कांग्रेस की राजनीतिक सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों से अपना घर तो सम्हल नहीं रहा है, जहां अंतर्कलह की नित-नई पटकथाएँ लिखी जा रही हैं। सत्ता और संगठन की परस्पर प्रतिद्वंद्विता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा की गई संगठनात्मक नियुक्तियों का आदेश 24 घंटों के भीतर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो, उस कांग्रेस के लोग भाजपा पर टीका-टिप्पणी करते शोभा नहीं देते। श्री कश्यप ने कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को साफ-साफ यह नसीहत दी है कि शीशे के घर में रह कर दूसरों के घरों पर पत्थर मारने की भूल न करें, बल्कि इस सवाल का जवाब प्रदेश को दे कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया पर उसके स्थान पर प्रदेश कांग्रेस का संगठन महामंत्री जिसे नियुक्त किया है उसे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी नहीं मानते हैं। कांग्रेसी बताएं कि अभी उनका महामंत्री कौन है? अंतर्कलह के चलते अपने नेताओं को लूप लाइन डालना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है और कांग्रेस अपनी इस प्रवृत्ति के तराजू पर भाजपा के राजनीतिक जनाधार व संगठन को तौलने का हास्यस्पद उपक्रम न करे।

कश्यप ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस की पहचान है, नियति है। अब तो कांग्रेस के लोगों को अपने पद नाम के साथ कोष्ठक में अपने-अपने गुट के नेताओं के नाम भी लिख देना चाहिए। कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते संगठन और सरकार के लोगों को अब यही करना बाकी रह गया है। श्री कश्यप ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में अपनी प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार, घोटाले और छल-कपट की राजनीति के चलते कांग्रेस अपनी हार मैदान में उतरने से पहले ही मान चुकी है और इसी अधीरता में ही वह प्रलाप के बेसुरे राग अलाप रही है।

जोड़-तोड़ करके अपने राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद में अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री पद का झुनझुना थमा कर गुटीय कलह को साधने की जो नाकाम कोशिश की है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने सांसद दीपक बैज

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आखिरकार बदल दिए गए। मोहन मरकाम के स्थान पर बस्तर के सांसद दीपक बैज को प्रदेश का नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो इस बात की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी

कि मोहन मरकाम की बदला जाएगा लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित बैठक में जब टी एस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय के साथ अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ तो लगा विधानसभा चुनाव तक मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। अब अचानक दीपक बैज के मान की घोषणा कर दी गई।अध्यक्ष बदलने के निर्णय से केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात पर मुहर लगा दी है। इस बात की चर्चा तो साल भर पहले से चल रही थी कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। पूर्व प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में संगठन और सत्ता के बीच तालमेल के अभाव को लेकर बहस भी हो गई थी। मुख्यमंत्री बैठक के बीच में चले गए थे। इसके बाद लगातार मोहन मरकाम ने संगठन पर मुख्यमंत्री को हावी होने नहीं दिया। प्रदेश महामंत्री प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला को अचानक हटाकर अमरजीत चावला को प्रभार सौंप दिया था, इस निर्णय से भी संगठन की गुटबाजी को हवा मिली। मुख्यमंत्री सहित कई नेता प्रदेशाध्यक्ष के निर्णय से खुश नहीं थे।

मतदाताओं को प्रलोभन से बचाने चुनाव आयोग ने बनाई रणनीति

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं को प्रत्याशियों के प्रलोभन से बचाने के लिए जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में इसके लिए रणनीति बनी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, विधानसभा चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के बेहतर समन्वय से कारगर सतर्कता प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। रीना बाबा कंगाले ने बताया कि सभी इंफोर्समेंट एजेंसियों को राज्य में संवेदनशीलता का आकलन करके रोड मैप तैयार करने, पिछले छह महीनों में किए गए जब्त की जानकारी तैयार करने, चुनाव में खर्च की संवेदनशीलता के साथ मैपिंग करने, रेलवे स्टेशनों, ट्रकों, बसों, व्यावसायिक वाहनों के साथ ही हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।बैठक में पुलिस विभाग, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्व सूचना निदेशालय, परिवहन विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय विमानपत्तन, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, डाक विभाग, विमानन विभाग और भारतीय रेल की स्थापित सतर्कता प्राधिकरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा हुई है। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विपिन मांझी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो आदि मौजूद रहे।

युवा ही भाजपा का अहंकार तोड़ेंगे : धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं से संवाद कार्यक्रम से युवाओं को धोखा देने वाले भाजपाई तिलमिला रहे हैं। भाजपा ने हमेशा युवाओं को गुमराह किया है धोखा दिया है

बरगलाया है और दिशाहीन करने का प्रयास किया है भूपेश बघेल की सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा रोजगार की दिशा में अनेक काम किए हैं बीते साढ़े 4 साल में 5लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया और आने वाले 5 वर्ष में रोजगार मिशन के माध्यम से 15लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है साथ में कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहे हैं अभी वन विभाग शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग सहित हर विभाग में सरकारी नौकरी की भर्तियां चल रही है यही भाजपा के लिए पीड़ा का विषय है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा मोदी के 9 साल पूरा होने पर युवाओं से चर्चा करने गए थे युवाओं ने तवज्जो नहीं दिया इससे भाजपा को समझ में आ गया है कि मोदी का जुमला और भाजपा का झूठ नहीं चलने वाला है।

16 जुलाई से लगातार बारिश होने के आसार

रायपुर । एक ओर पूरे उत्तर भारत और हिमाचल में लोग भारी वर्षा से परेशान है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से आने वाले दो से तीन दिनों में अच्छी बारिश शुरू होने की उम्मीद है, कुछ क्षेत्रों में तो भारी वर्षा भी संभावित है।मौसम विभाग का कहना है कि रविवार 16 जुलाई से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगातार वर्षा के आसार है। वर्षा की गतिविधि बस्तर क्षेत्र से शुरू होकर प्रदेश भर में बढ़ेगी। मालूम हो कि मानसून की लेटलतीफी से प्रदेश में अभी एक जून से लेकर अब तक की स्थिति में 16 फीसद बारिश कम हुई है, आने वाले दिनों में भरपुर बारिश की उम्मीद है। बुधवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बुंदाबांदी भी हुई। कटेकल्याण 4 सेमी, मरवाही-दंतेवाड़ा-पथरिया 3 सेमी, मनोरा-नारायणपुर-ओरछा 2 सेमी वर्षा हुई। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में मौसम की गतिविधि अब बढ़ने वाली है और भरपुर वर्षा की उम्मीद है।रायपुर के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। रायपुर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश भर में एआरजीसक्ती में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

युवाओं से भेंट नहीं सेट मुलाकात कार्यक्रम है : ठाकने

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता नलीनेश ठोकने ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के बाद अब युवाओं से चर्चा करना चाहा है यह भेंट मुलाकात नहीं सेट मुलाकात कार्यक्रम है। क्योंकि यह वह पहले ही तय करके निकलेंगे कि किन से मिलना है, वह क्या बोलेगा और क्या उत्तर देना है। ठाकने ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जब भी मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने आए तो उन्हें यह जरुर पूछे कि जन घोषणा पत्र जारी करते समय बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी विधानसभा चुनाव से ठीक तीन माह पहले उन्हें क्यों याद आया। ठाकने ने कहा कि कांग्रेसी स्पष्ट करें कि आज उनका महामंत्री कौन है जिसकी नियुक्ति मोहन मरकाम व कुमारी शैलजा ने की है। मुख्यमंत्री पहले अपने घर को सम्हालें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करें।

भाजपा के किसान मोर्चा चौपाल लगाकर पढ़ा रहा धान का गुणा-भाग

रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा के किसान मोर्चा ने धान और किसान मोर्चे पर सक्रियता तेज कर दी है। मोर्चा ने किसानों को धान का गुणा-भाग समझाने का जिम्मा उठाया है। गांव-गांव में किसानों के साथ मोर्चा चौपाल लगा रहा है।

इसमें मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, किसान सम्मान निधि और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका आदि की जानकारी दी

जा रही है। प्रदेश में अब तक 1,512 में किसान चौपाल आयोजित हो चुके हैं।

प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने बताया कि जून से महासंपर्क अभियान के तहत धान खरीदी केंद्रों को इकाई मानकर खाद गोदामों,सामुदायिक भवनों या बरगद पेड़ के नीचे चौपाल लगा रहे हैं। इसमें 30 से 100 किसान शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में धान खरीदी केंद्र 2,385 केंद्र हैं। इनमें दो हजार केंद्रों तक पहुंचने का लक्ष्य है। चौपाल लगाने से पहले कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

चौपाल में किसानों को दे रहे ये जानकारी

केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि उपज के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 36 लाख टन चावल सेंट्रल पूल में लिया था, मगर आज कांग्रेस सरकार में भी बिना भेद-भाव के 62 लाख टन यानी 94 लाख टन धान की खरीदी केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। केंद्र सरकार किसानों को हर साल छह हजार रुपये सम्मान निधि देती है। इस तरह 11 बिंदुओं पर किसानों को समझाया जा रहा है।

धान और किसान का राजनीति में महत्व

प्रदेश में राजनीति के लिए धान-किसान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के मुद्दे को लेकर प्रदेश में सरकार बनती और बिगड़ती भी है। वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा ने 300 रुपये बोनस की घोषणा की थी, भाजपा की सरकार बनी मगर किसानों को यह राशि नहीं मिली। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 2,500 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी और भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा था।

लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य: राज्यपाल हरिचंदन

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन अपने तीन दिवसीय ओडिशा प्रवास के दौरान ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह भुवनेश्वर के गीतगोबिंद सदन में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री प्रदीप किशोर दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ समाज के लिए किये गये योगदान को याद किया और स्वर्गीय दास

को एक ईमानदार नेता बताया।

समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्वस्थ एवं सुंदर देश का निर्माण करने के लिए में प्रत्येक नागरिक को योगदान देना चाहिए। योग्य लोगों को ही राज्य एवं देश पर शासन करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्कता है। स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता का अधिकार है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी को भागीदारी करने का अनुरोध किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.